

# दिल्ली राजपत्र



# Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 125]	दिल्ली, सोमवार, जुलाई 23, 2012/श्रावण 1, 1934	[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 100
No. 125]	DELHI, MONDAY, JULY 23, 2012/SHRAVANA 1, 1934	[N.C.T.D. No. 100

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह ( पुलिस-II ) विभाग

आदेश

दिल्ली, 23 जुलाई, 2012

फा. सं. 2/1/1988/गृह पुलिस-II/पार्ट/4056.—चूंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा करना आवश्यक है :-

इसलिए, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 2 के खण्ड (ई) के साथ पठित धारा 3 की उप-धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल यह निर्देश देते हैं कि दिल्ली पुलिस आयुक्त भी 19-7-2012 से 18-10-2012 तक की अवधि के दौरान उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) की शक्तियों का प्रयोग निरोध प्राधिकारी के रूप में कर सकते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,  
बी. के. तिवारी, उप-सचिव (गृह)

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT  
ORDER

Delhi, the 23rd July, 2012

F. No. 2/1/1988/HP-II/Part/4056.—Whereas, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is satisfied that it is necessary to do so :-

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 3, read with clause (c) of Section 2 of the National Security Act 1980, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to direct that during the period 19-7-2012 to 18-10-2012, the Commissioner of Police, Delhi may also exercise the powers of detaining authority under sub-section (2) of Section 3 of the aforesaid Act.

By Order and in the Name of the Lt. Governor  
of the National Capital Territory of Delhi,  
B. K. TIWARI, Dy. Secy. (Home)

## विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

## अधिसूचनाएं

दिल्ली, 23 जुलाई, 2012

फा. सं. 14(15)/एलए-2011/Cons2law/110.—भारत के राष्ट्रपति की दिनांक 4 जुलाई, 2012 को मिली अनुमति के पश्चात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जन साधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :—

**“भारतीय मुद्रांक शुल्क (दिल्ली संशोधन) अधिनियम, 2012  
(2012 का दिल्ली अधिनियम 10)**

(4 जून, 2012 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)

[4 जुलाई, 2012]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा प्रवृत्त भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 में और आगे संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारम्भ.—(1) इस अधिनियम को भारतीय मुद्रांक (दिल्ली संशोधन) अधिनियम, 2012 कहा जाए ।

(2) यह समस्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विस्तारित होगा ।

(3) यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यथा नियत तारीख से प्रभावी होगा ।

2. अनुसूची 1क का संशोधन.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा प्रवृत्त भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम 3) में अनुसूची 1क के भाग संख्या (10) के खंड (क) एवं (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

## 10. किसी कम्पनी के संस्था नियम

प्रलेख का वर्णन	पेपर स्टाम्प ड्यूटी
(क) जब कम्पनी की प्राधिकृत पूंजी एक लाख रुपये से अधिक नहीं होती है;	प्राधिकृत शेयर पूंजी का 0.15 प्रतिशत
(ख) दूसरे मामलों में;	पच्चीस लाख रुपये की अधिकतम मौद्रिक सीमा सहित प्राधिकृत शेयर पूंजी का 0.15 प्रतिशत
(ग) जब प्राधिकृत शेयर पूंजी बढ़ती है;	पच्चीस लाख रुपये की अधिकतम मौद्रिक सीमा सहित प्राधिकृत शेयर पूंजी में हुई बढ़ोतरी का 0.15 प्रतिशत

## DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

## NOTIFICATIONS

Delhi, the 23rd July, 2012

F. No. 14(15)/LA-2011/Cons2law/110.—The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the President of India on 4th July, 2012 and is hereby published for general information :—

**"THE INDIAN STAMP (DELHI AMENDMENT) ACT, 2012****(DELHI ACT 10 OF 2012)**

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the  
4th June, 2012)

[4th July, 2012]

Further to amend the Indian Stamp Act, 1899 in its application to the National Capital Territory of Delhi.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows :—

**1. Short title, extent and commencement.**—(1) This Act may be called the Indian Stamp (Delhi Amendment) Act, 2012.

(2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.

(3) It shall come into force on such date as the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi may, by notification in the Delhi Gazette, appoint.

**2. Amendment of Schedule I-A.**—In the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899) as in force in the National Capital Territory of Delhi, in Schedule I-A, in Article No. 10 for clauses (a) and (b), the following clauses shall be substituted, namely :—

**10. ARTICLES OF ASSOCIATION OF A COMPANY**

Description of Instrument	Proper Stamp Duty
(a) When the Authorised Capital of the Company does not exceed rupees one lakh;	0.15% of the Authorised share capital
(b) In other cases;	0.15% of the Authorised share capital with a monetary ceiling of rupees twenty five lakhs
(c) When the Authorised share capital is increased	0.15% of the increase in Authorised share capital with a monetary ceiling of rupees twenty five lakhs."

फा. सं. 14( 16 )/एलए-2011/Cons2law/98.—उपराज्यपाल, दिल्ली की दिनांक 11 जुलाई, 2012 को मिली अनुमति के पश्चात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम को जन साधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :—

**“इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2012  
(2012 का दिल्ली अधिनियम 09)**

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा दिनांक 31 मई, 2012 को यथा पारित)

[11 जुलाई, 2012]

महिलाओं के लिये इंदिरा गांधी दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय के रूप में इन्दिरा गांधी प्रौद्योगिकी संस्थान के पुनर्गठन के लिए, इसे दिल्ली में गैर संबंधन शिक्षण तथा शोध विश्वविद्यालय के रूप में समावेशन के लिए इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, अनुप्रयुक्त विज्ञान, प्रबंधन तथा इससे सम्बद्ध क्षेत्रों में ध्यान देने सहित व्यवसायिक शिक्षा के उभरते क्षेत्रों में अध्ययन, शोध, प्रौद्योगिक, नवीनता, इन्क्यूबेशन तथा विस्तार कार्य को सुविधाजनक बनाने तथा बढ़ावा देने के लिए और इससे संबंधित क्षेत्रों में तथा इनसे सम्बद्ध या प्रासंगिक अन्य विषयों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए एक अधिनियम।

जबकि इंदिरा गांधी प्रौद्योगिकी संस्थान, गुरु गोविन्द सिंह विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का एक घटक महाविद्यालय है:

और जबकि, उक्त संस्था को एक विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करना समीचीन है ताकि यह ज्ञान तथा शिक्षण में उन्नति तथा इसके प्रसार को बढ़ावा देने के लिए शिक्षण तथा अध्ययन के पाठ्यक्रमों की विभिन्न विधाओं में अध्ययन और शोध केन्द्र के रूप में अधिक कुशलतापूर्वक कार्य करने में समर्थ हो सके। इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, अनुप्रयुक्त, विज्ञान तथा प्रबंधन विज्ञान आदि उद्योग के लिए प्रासंगिक शोध एवं अन्वेषण को बढ़ावा देने के क्षेत्र में उच्च शिक्षा तथा शोध की मांग को पूरा करना जिससे समाज तथा राष्ट्र की सेवा के लिए संभावनाएं और अवसर उपलब्ध हो सके।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ।	1(1)	इस अधिनियम को महिलाओं के लिये इंदिरा गांधी दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 कहा जाएगा।
	(2)	यह सरकारी राजपत्र में सरकार द्वारा नियत तारीख को अधिसूचना द्वारा लागू होगा।
परिभाषाएं।	2.	जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो तब तक इस अधिनियम में :—

	(क)	"शैक्षणिक परिषद्" का अर्थ विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद् से है;
	(ख)	"शैक्षणिक स्टाफ" का अर्थ स्टाफ का ऐसा वर्ग जो कि विश्वविद्यालय का शैक्षणिक स्टाफ होने के लिए संविधि द्वारा निर्दिष्ट हो;
	(ग)	"प्रबंधन बोर्ड" का अर्थ विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड से है;
	(घ)	"कैम्पस" का अर्थ निदेश, अनुसंधान या दोनों के लिए व्यवस्था करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या गठित इकाई से है;
	(ङ)	"कुलाधिपति" "कुलपति" तथा "उप-कुलपति" का अर्थ क्रमशः विश्वविद्यालय का कुलाधिपति, कुलपति तथा उप-कुलपति से है;
	(च)	"केन्द्र" का अर्थ
	(छ)	"परिषद्" का अर्थ विश्वविद्यालय की परिषद् से है;
	(ज)	"दिल्ली" का अर्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से है;
	(झ)	"विभाग" का अर्थ विश्वविद्यालय के अध्ययन विभाग से है;
	(ञ)	"कर्मचारी" का अर्थ विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति से है;
	(ट)	"वित्त समिति" का अर्थ विश्वविद्यालय की वित्त समिति से है;
	(ठ)	"सरकार" का अर्थ भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एवं अनुच्छेद 239कक के अन्तर्गत यथापदनामित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से है;
	(ड)	"हॉल" का अर्थ विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के रहने या कॉरपोरेट लाइफ की इकाई से है;
	(ढ)	"संस्थान" का अर्थ विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित संस्थान से है;
	(ण)	"उपराज्यपाल" का अर्थ भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एवं अनुच्छेद 239कक के अन्तर्गत यथापदनामित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से है;
	(त)	"कदाचार" का अर्थ संविधि द्वारा निर्धारित कदाचार से है;
	(थ)	"अधिसूचना" का अर्थ सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से है;
	(द)	"योजना बोर्ड" का अर्थ विश्वविद्यालय के योजना बोर्ड से है;
	(ध)	"निर्धारित" का अर्थ इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाई गई/बनाये गये संविधियां या अध्यादेश या विनियमों से है;

	(न)	"कुलसचिव" का अर्थ विश्वविद्यालय के कुलसचिव से है;
	(प)	"संविधि", "अध्यादेश" तथा "विनियम" का अर्थ तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय का क्रमशः संविधियों, अध्यादेशों तथा विनियमों से है;
	(फ)	"विश्वविद्यालय" का अर्थ इस अधिनियम के अन्तर्गत यथानिगमित महिलाओं के लिये इंदिरा गांधी दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय से है; तथा
	(ब)	"विश्वविद्यालय शिक्षक" का अर्थ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तथा सहायक प्रोफेसर विश्वविद्यालय में निदेश देने या अनुसंधान हेतु नियुक्त किया गया हो तथा संविधियों द्वारा शिक्षक के रूप में पदनामित किया गया हो।
विश्वविद्यालय का सम्मिलन	3.(1)	सरकार द्वारा यथानिर्धारित तारीख से सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा "इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय" के नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, जिसमें कुलाधिपति, कुलपति, परिषद् के प्रथम सदस्य, विश्वविद्यालय का प्रबंधन बोर्ड तथा शैक्षणिक परिषद् तथा विश्वविद्यालय की वित्त समिति तथा ऐसे सभी सदस्य सम्मिलित होंगे जो यहां बाद में ऐसे कार्यालय या ऐसे सदस्यों के रूप में नियुक्त किए जा सकते हैं जब तक वे ऐसे कार्यालय या सदस्यता में बने रहेंगे।
	(2)	विश्वविद्यालय का एक निगमित निकाय होगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार तथा शक्ति सहित इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार सामान्य मुहर जो कि संपत्ति तथा संविदा प्राप्त करने, धारण करने एवं निपटान हेतु तथा उक्त नाम द्वारा मुकद्दमा चलाने या चलवाने के लिए प्रयुक्त की जा सकती है।
	(3)	विश्वविद्यालय, व्यवसायिक शिक्षा पर केन्द्रित उभरते क्षेत्रों में अध्यापन तथा शोध से सम्बद्ध एक उत्कृष्टता केन्द्र होगा लेकिन इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, अनुप्रयुक्त विज्ञान तथा प्रबंधन तक सीमित नहीं है तथा इन संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए शिक्षा तथा शोध में अन्तर विधाओं को बढ़ावा देगा।
	(4)	विश्वविद्यालय प्रशासनिक रूप से स्वायत्त होगा तथा छात्राओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए दिल्ली सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करेगा और इस प्रकार अपने प्रशासन तथा यथानिर्धारित प्रशासनिक नीतियों, पद्धतियों सहित दिल्ली सरकार से पूंजीगत तथा प्रचालनात्मक व्यय के लिए निधि प्राप्त करेगा।
	(5)	विश्वविद्यालय प्रारंभ में कश्मीरी गेट परिसर से कार्य करेगा। विश्वविद्यालय को सरकार द्वारा एक उपयुक्त भू-खंड उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार प्रारंभ में अवसंरचना की स्थापना के लिए निधि उपलब्ध कराएगी जिसमें भूमि विकास, वास्तुविद् संबंधी अभिकल्पन, भवन, उपकरण तथा अन्य आवश्यकताएं।

विश्वविद्यालय के समावेशन का प्रभाव।	4.	इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर तथा से—
	(क)	किसी विधि में (इस अधिनियम से भिन्न) या किसी संविदा में या अन्य प्रलेख में इंदिरा गांधी प्रौद्योगिकी संस्थान सम्बन्धी किसी उल्लेख/संदर्भ को विश्वविद्यालय के सन्दर्भ के रूप में मान लिया जायेगा;
	(ख)	इंदिरा गांधी प्रौद्योगिकी संस्थान की या सम्बन्धित समस्त सम्पत्ति, चल तथा अचल विश्वविद्यालय में निहित होगी;
	(ग)	इंदिरा गांधी प्रौद्योगिकी के सभी अधिकार एवं देयताएं विश्वविद्यालय को अन्तरित की जाएगी और विश्वविद्यालय के अधिकार तथा देयताएं होंगे/होगी;
	(घ)	इंदिरा गांधी प्रौद्योगिकी द्वारा नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति ऐसे प्रारंभ होने से पूर्व विश्वविद्यालय में अपने पद या सेवा पर उतने कार्यकाल तक उसी पारिश्रमिक पर और उन्हीं शर्तों पर और पेंशन छुट्टी, उपदान, भविष्य निधि और अन्य मामलों सम्बन्धी वही अधिकारों एवं विशेषाधिकारों पर बने रहेंगे जैसाकि उसके पास है यदि यह अधिनियम पारित नहीं किया गया होता था और तब तक ऐसा करने के लिये बने रहेंगे और जब तक उसका रोजगार समाप्त नहीं हो जाता है या उसने रोजगार संबंधी विश्वविद्यालय की शर्तों को चुन लिया है; एवं
	(ङ)	इस अधिनियम में कुछ भी रहते हुए इस अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय की स्थापना से पूर्व जिन वर्तमान विद्यार्थियों ने इंदिरा गांधी प्रौद्योगिकी की कक्षाओं में भाग लिया वे अपने नामांकन के अन्तर्गत अपने शैक्षिक पाठ्यक्रम तथा अध्ययन कार्यक्रम जारी रखेंगे तथा उनका संबंध गुरु गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से रहेगा, जो उनके लिये परीक्षाएं आयोजित करके जिन अध्ययन पाठ्यक्रम एवं कार्यक्रमों में इस समय व अध्ययन कर रहे हैं उन्हें सफलता पूर्वक पूरा करने पर उन्हें उपाधियां प्रदान करेगा;
	(च)	विश्वविद्यालय द्वारा सहायता अनुदान में से व्यय सरकार द्वारा अनुमोदित सहायता की पद्धति के अनुसार, समय-समय पर यथा संशोधित जीएफआर, 2005 के उपबंध तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी अनुदेशों/मार्गनिर्देशों/निर्देशों के अनुसार किए जाएंगे। वे सरकार में यथा प्रचलित नियमावली के वित्तीय नियमों का तब तक पालन करेंगे जब तक वे सरकार द्वारा अनुमोदित अपने नियम नहीं बना लेते।
अधिकार क्षेत्र	5.	इस अधिनियम के अधीन या इसके द्वारा उपबंधित अन्यथा को छोड़कर उन क्षेत्रों की सीमाएँ जिनमें विश्वविद्यालय अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा वे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की होगी।
विश्वविद्यालय का उद्देश्य	6.	विश्वविद्यालय के उद्देश्यः—
	(1)	इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिक, विज्ञान, प्रबंधन तथा समक्ष क्षेत्रों के अनुरूप व्यवसायिक शिक्षा विकसित करना तथा व्यापक शिक्षा प्रदान करना परंतु यह इन्हीं तक सीमित न हो;

	(2)	डिग्री, डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु शिक्षा को सरल बनाना तथा प्रोत्साहित करना;
	(3)	इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिक, विज्ञान, प्रबंधन तथा संबंधित क्षेत्रों तथा प्रासंगिक क्षेत्रों में श्रेष्ठता हासिल करना;
	(4)	इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिक, विज्ञान, प्रबंधन तथा संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में उच्चतर शिक्षा, अनुसंधान तथा नवाचार के केन्द्र स्थापित करना;
	(5)	उत्पाद, सर्विस तथा ठेकेदारी प्रथा को विकसित करना;
	(6)	उद्योगों के लिये प्रासंगिक होना एवं भारत तथा विदेश में शैक्षिक समुदाय पर प्रभाव पैदा करना;
	(7)	भारत और विदेश में अध्यापन तथा अनुसंधान कार्यक्रमों (दोहरी डिग्री सहित) में सहयोग के लिए विश्वविद्यालय, उद्योगों, अनुसंधान तथा विकासशील संगठनों तथा अन्य विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के बीच संबंध स्थापित करना;
	(8)	इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिक, विज्ञान, प्रबंधन तथा संबंधित क्षेत्रों में संकाय तथा छात्रों के माध्यम से वैश्विक ध्यान आकर्षित करना;
	(9)	नवाचार केन्द्र, नॉलेज पार्क तथा टेक्नोलॉजी इन्क्यूबेटर स्थापित करना ताकि टेक्नो-ठेकेदारी प्रथा, नवाचार तथा नए उत्पाद विकसित करने में तेजी लाई जा सके।
	(10)	समय-समय पर विशेषज्ञों के लैक्चर, सेमिनार, संगोष्ठियां, कार्यशाला, सम्मेलन तथा ग्रीष्म एवं शीतकालीन विद्यापीठ, लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित कर ज्ञान का प्रसार करना तथा राष्ट्र निर्माण में सहयोग करना और संकाय का विकास करना।
	(11)	संस्कृति एवं नैतिक मूल्यों का प्रचार एवं विकास करना ताकि व्यवसायिक नैतिकता, अनुसंधान, अखंडता, व्यवसायिक पेशेवरों के लिए विश्वस्तरीय स्वीकार्य व्यवसायिक नैतिक एवं उद्देश्यों का प्रचार एवं विकास किया जा सके;
	(12)	इलेक्ट्रॉनिक स्रोतों सहित विश्वविद्यालय के शैक्षणिक क्षेत्रों से संबंधित पत्रिकाएं, शोध प्रबंध, अध्ययन, पुस्तक, रिपोर्ट, जर्नल तथा अन्य साहित्य का प्रकाशन करना;
	(13)	इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिक, विज्ञान, प्रबंधन तथा संबंधित अध्ययन, प्रशिक्षण परियोजना तथा शिल्प विज्ञान स्थानान्तरण कार्यक्रम आयोजित करना;
	(14)	विश्वविद्यालय के किसी भी उद्देश्य या सभी के लिए सहायक या आकस्मिक, आवश्यक जैसे कार्य करना।



विश्वविद्यालय की शक्तियाँ एवं कार्य	7.	विश्वविद्यालय की निम्न शक्तियाँ होंगी और नामतः निम्न कार्य करेगा:—
	(i)	समय-समय पर विश्वविद्यालय के अनुरूप शिक्षा के प्रसार के लिए अनुदेश जारी करना, ज्ञान एवं दक्षता की उन्नति एवं प्रचार के लिए तथा अनुसंधान के लिए प्रावधान एवं निर्धारण करना;
	(ii)	परीक्षा आयोजित करना तथा विश्वविद्यालय निर्धारण के अनुसार शर्तों के अनुरूप डिग्री, डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्र प्रदान करना और परीक्षा के आधार पर समय-समय पर डिग्री तथा अन्य शैक्षिक पदक या उपाधि प्रदान करना या मूल्यांकन या व्यक्ति पर परीक्षण का कोई अन्य तरीका तथा अच्छे एवं पर्याप्त कारण के लिए ऐसे पुरस्कार को वापस लेना;
	(iii)	सम्मानार्थ डिग्री या अन्य उपाधि प्रदान करना;
	(iv)	अतिरिक्त भित्ति अध्ययन तथा विस्तारित सर्विस आयोजित करना तथा प्रतिज्ञा करना;
	(v)	विश्वविद्यालय के अंतर्गत शैक्षिक, अनुसंधान, प्रशासनिक, तकनीकी, लिपिक वर्गीय तथा अन्य पदों का सृजन करना तथा निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप नियुक्ति करना;
	(vi)	विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, सह-प्रोफेसर या सहायक प्रोफेसर को शिक्षक के रूप में मान्यता देना;
	(vii)	विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त शैक्षिक या प्रशासनिक स्टॉक के अन्य सदस्यों तथा शिक्षकों की सेवा के लिए निबंधन एवं शर्तें उपलब्ध कराना;
	(viii)	किसी अन्य विश्वविद्यालय, प्राधिकरण या उच्च शिक्षा के संस्थान, अनुसंधान प्रयोगशाला, उद्योग के साथ इस प्रकार से सहयोग या सम्बद्ध होना तथा जैसाकि विश्वविद्यालय द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्धारित है;
	(ix)	इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिक, विज्ञान, प्रबंधन एवं अन्य विषयों में मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ (अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट तथा अनुसंधान) सभी स्तरों पर शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए केन्द्र स्थापित करना;
	(x)	अधिसंख्य सीटों के लिए निर्धारित, विदेशी छात्रों के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों तथा कार्यक्रमों के लिए अंदरूनी अनुमोदन लेना, भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ), विदेशों में रहने वाले भारतीयों (एनआरआई) तथा स्वयं वित्तीय सहायता तथा प्रायोजित छात्रों की फीस का समय-समय पर निर्धारण किया जाए;
	(xi)	किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत व्यक्ति को निर्धारित के लिए विश्वविद्यालय के शिक्षक के रूप में नियुक्त करना;

(xii)	अकादमिक कार्य प्रणाली के लिए अकादमिक निकाय बनाना तथा उन्हें निर्धारित तरीके से मानदेय देना;
(xiii)	अनुदेश प्रदान करने या अनुसंधान के पर्यवेक्षण या दोनों के लिए भारत तथा विदेश में अनुदेशों के साथ सहयोग तथा प्रचार सहयोग को लागू करना;
(xiv)	संस्थान, कैम्पस को स्थापित, अनुरक्षण करने के लिए तथा शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा विस्तार के अन्य केन्द्र स्थापित करना जोकि विश्वविद्यालय द्वारा उचित समझा गया हो;
(xv)	केन्द्रीय सुविधाएं जैसे- कम्प्यूटर केन्द्र, इंस्ट्रुमेंटेशन सेंटर, सैट्रल वर्कशाप, सैट्रल लाइब्रेरी, ऑडीटोरियम इत्यादि स्थापित करना;
(xvi)	विभिन्न विषयों के लिए पाठ्यक्रम विकास सेल स्थापित करना ताकि प्रशिक्षण सामग्री मुद्रण एवं इलेक्ट्रॉनिक फार्म में तैयार की जा सके;
(xvii)	अनुसंधान तथा परामर्शदात्री सेवा के लिए प्रावधान करना तथा इस उद्देश्य के लिए अन्य संस्थानों या निकायों के साथ ऐसे अनुबंधों में प्रवेश करना जैसाकि विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित है;
(xviii)	विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए प्रणाली एवं मानक निर्धारित करना जिसमें परीक्षा, मूल्यांकन या चयन की कोई प्रक्रिया सम्मिलित हो सकती है;
(xix)	फेलोशिप, स्कॉलरशिप, स्टूडेंटशिप, मैडल तथा पुरस्कार की प्रथा प्रारंभ करना;
(xx)	फीस तथा अन्य प्रभारों के भुगतान की निर्धारित मांग करना तथा प्राप्त करना;
(xxi)	संकाय स्टॉफ, छात्रों तथा स्कालरों के लिए हाल, होस्टल, निवास इत्यादि का स्थापन, अनुरक्षण तथा प्रबंधन;
(xxii)	विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास को निर्धारित, पर्यवेक्षण तथा नियंत्रित करना;
(xxiii)	छात्रों की आचार संहिता निर्धारित और नियंत्रित करना और विश्वविद्यालयीय के छात्रों के बीच अनुशासन लागू करना और उनके स्वास्थ्य, कल्याण तथा संस्कृति एवं कारपोरेट लाइफ को बनाए रखने की व्यवस्था करना;
(xxiv)	इसके कर्मचारियों के लिए नीतिशास्त्र की संहिता, आचार संहिता तथा अनुशासन नियम एवं छात्रों के लिए अनुशासन आचार संहिता निर्धारित करना;
(xxv)	विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के कार्य एवं संहिता को नियंत्रित करना तथा आवश्यकतानुसार इस संबंध में अनुशासनात्मक उपाय करना;
(xxvi)	विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं सामान्य कल्याण को बनाए रखने की व्यवस्था करना;

	(xxvii)	विश्वविद्यालय के लिए कार्पस निधि का सृजन करना और एलूमनी उद्योग तथा अन्य राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय फाउंडेशन, संगठनों से प्राप्त अंशदान का पूरा या आंशिक स्थानान्तरण जैसाकि विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड द्वारा अनुमोदित है और ऐसे कार्पस निधि की उपयोगिता के लिए बहुलकता का निर्णय करना;
	(xxviii)	व्यक्तियों से दान, अंशदान तथा उपहार प्राप्त करना और उनके पीछे नाम लिखना जैसे— कुर्सी, संस्थान, भवन और जैसा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया गया है, किसका उपहार या विश्वविद्यालय को दिया अंशदान विश्वविद्यालय की राशि के अनुरूप हो;
	(xxix)	विश्वविद्यालय के उद्देश्य के लिए आवश्यकता या सुविधा के अनुसार उपहार, क्रय, बीज, किराए या अन्यथा किसी प्रकार से चल या अचल संपत्ति पर कब्जा और विश्वविद्यालय के उद्देश्य के लिए आवश्यकतानुसार भवन का अनुरक्षण तथा मरम्मत, निर्माण, सुधार, परिवर्तन, ढाहना आदि करना;
	(xxx)	विश्वविद्यालय की चल एवं अचल संपत्ति के संपूर्ण या किसी हिस्से को बेचना, पट्टे पर देना, विनियम करना, किराए पर देना या स्थानान्तरित करना, बशर्तें इसे स्थानान्तरण या निपटान के लिए सरकार से लिखित रूप में पूर्वानुमोदन ले लिया गया हो;
	(xxxix)	सरकार के अनुमोदन से, विश्वविद्यालय की संपत्ति की प्रतिभूति विश्वविद्यालय के उद्देश्य के लिए राशि उधार लेना;
	(xxxii)	विशेषज्ञ के क्षेत्र, शिक्षा के स्तरों तथा तकनीकी एवं लघु एवं दीर्घ कालीन अवधि दोनों के लिए अन्य श्रम शक्ति के प्रशिक्षण के उद्देश्यों के संबंध में आवश्यकताओं का आकलन करना और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यक्रम प्रारंभ करना;
	(xxxiii)	अनुपूरक सुविधाएं प्रदान करने के लिए उद्योग तथा अन्य विशेषज्ञ एजेंसियों की सहभागिता को सूचीबद्ध करने के उपाय प्रारंभ करना;
	(xxiv)	'दूरस्थ शिक्षा' तथा 'मुक्त शिक्षा शैली' के माध्यम से शिक्षा तथा अनौपचारिक या मुक्त शिक्षा शैली का औपचारिक शिक्षण में तथा इसके विपरीत प्रवेश की व्यवस्था करना;
	(xxxv)	सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त हुए पदों पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों की नियुक्ति करना जिन्होंने निर्धारित निबंधन एवं शर्तों पर बहुमूल्य सेवा प्रदान की है और
	(xxxvi)	विश्वविद्यालय के किसी उद्देश्य के लिए वे सारे कार्य करना जो आवश्यक हैं या आकस्मिक हैं या विश्वविद्यालय की किसी शक्ति या उद्देश्य को हासिल करने के लिए जरूरी हैं।
विश्वविद्यालय समस्त वर्गों, जातियों एवं धर्मों के लिए खुला है	8.(1) (क)	छात्र— विश्वविद्यालय केवल महिला छात्रों की भर्ती के लिए खुला रहेगा या स्नातकों के लिए, तथा विश्वविद्यालय के लिए तथा बाध्यकर नहीं होगा कि वो किसी भी छात्र पर धर्म या व्यवसाय या राजनैतिक मत का दबाव डाले या अपनाए ताकि जिसके आधार पर छात्र को विश्वविद्यालय में दाखिला मिल सके;

	(2)	समाज के कमजोर वर्ग की महिला छात्रों तथा विशेष रूप से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को दाखिले के लिए विशेष प्रावधानों हेतु विश्वविद्यालय को यह सैक्शन रोक नहीं सकता है;
	(3)	किसी भी राष्ट्र की महिला छात्रों के लिए विश्वविद्यालय खुला रहेगा और उन्हें निर्धारित तरीके से दाखिला दिया जाएगा।
	(ख)	कर्मचारी—(1) विश्वविद्यालय किसी भी लिंग के व्यक्तियों या जाति, धर्म, जात या वर्ग के लिए खुला रहेगा और विश्वविद्यालय के लिए कानूनी रूप से जरूरी नहीं है कि वो धर्म या व्यवसाय या राजनैतिक मत के लिए किसी व्यक्ति की परीक्षा लें ताकि उसे विश्वविद्यालय के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सके या सुविधा हेतु किसी अन्य कार्यालय में लगाया जा सके।  (2) समाज के कमजोर वर्ग से संबंधित व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान हेतु विश्वविद्यालय को विधि संगत कोई नहीं रोक सकता है विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को।
विश्वविद्यालय में शिक्षण।	9.(1)	विश्वविद्यालय के डिग्री डिप्लोमा एवं प्रमाण-पत्र कार्यक्रमों से संबंधित शिक्षण को अध्यादेश एवं विनियम के अनुरूप संचालित किया जाए।
	(2)	कोर्स तथा पाठ्यक्रम तथा ऐसे कोर्स एवं पाठ्यक्रम के शिक्षण को आयोजित करने के लिए जिम्मेवार प्राधिकारी अध्यादेश द्वारा यथा निर्धारित होगा।
विश्वविद्यालय का विजिटर।	10.(1)	भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति विश्वविद्यालय के विजिटर होंगे।
	(2)	विश्वविद्यालय तथा दिल्ली में विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य विश्वविद्यालय के बीच उत्पन्न कोई विवाद को विजिटर के पास भेजा जायेगा जिसका निर्णय अंतिम होगा तथा दोनों पक्षों पर बाध्य होगा।
विश्वविद्यालय का कुलाधिपति।	11.(1)	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे;
	(2)	कुलाधिपति, यदि उपस्थित हो, डिग्री प्रदान करते समय विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेंगे;
	(3)	कुलाधिपति को ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को जैसा वह निदेश दे, विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा पोषित किसी संस्था/केन्द्र इसके भवनों, प्रयोगशालाओं एवं उपकरणों तथा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा, शिक्षण एवं किए जाने वाले अन्य कार्यों की जाँच करवाने का अधिकार होगा तथा विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त या किन्हीं मामलों में उसी पद्धति से जाँच करवाने का अधिकार होगा;

	(4)	कुलाधिपति प्रत्येक मामले में विश्वविद्यालय को जाँच पड़ताल करवाने की सूचना देगा तथा विश्वविद्यालय को ऐसी सूचना प्राप्त होने पर कुलाधिपति को ऐसा प्रतिवेदन करने का अधिकार होगा जैसा वह सूचना में यथाविनिर्दिष्ट अवधि के अन्दर उचित समझे;
	(5)	प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् कुलाधिपति उपधारा (3) में यथा उल्लिखित जाँच एवं निरीक्षण करवा सकता है;
	(6)	जहाँ कुलाधिपति द्वारा कोई निरीक्षण या जाँच करवाई जानी है, वहाँ विश्वविद्यालय को किसी प्रतिनिधि को नियुक्त करने का अधिकार होगा जिसे उपस्थित होने तथा ऐसी जाँच एवं निरीक्षण में सुनवाई का अधिकार होगा;
	(7)	कुलाधिपति उपधारा (3) में यथा उल्लिखित ऐसी जाँच या निरीक्षण के परिणाम के संदर्भ में कुलाधिपति को सूचित कर सकता है तथा कुलाधिपति प्रबंधन बोर्ड को कुलाधिपति के विचारों सहित ऐसी सलाह पर जैसा कुलाधिपति उस पर की जाने वाली कार्रवाई के लिए अपेक्षित समझे, भेजेगा;
	(8)	प्रबंधन बोर्ड कुलपति के माध्यम से कुलाधिपति को ऐसी कार्रवाई से सूचित करेगा जो कि ऐसे निरीक्षण या जाँच के परिणाम पर की जानी प्रस्तावित हो या की गई हो;
	(9)	जहाँ प्रबंधन बोर्ड पर्याप्त समय में कुलाधिपति की संतुष्टि के लिए कार्रवाई नहीं करता, वहाँ चान्सलर जैसा उचित समझे निदेश जारी कर सकता है तथा प्रबंधन बोर्ड ऐसे निदेशों का पालन करेगा;
	(10)	<p>इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कुलाधिपति लिखित में आदेश द्वारा विश्वविद्यालय की किसी भी कार्यवाहियों को रद्द कर सकता है जो इस अधिनियम, संविधि अथवा अध्यादेशों के अनुरूप नहीं है।</p> <p>शर्त यह है कि कोई ऐसा आदेश करने से पूर्व कुलाधिपति विश्वविद्यालय से पूछ सकेंगे कि ऐसा आदेश न करने के कारण क्यों नहीं बताया जाना चाहिये और दर्शाये गये कारण पर विचार किया जायेगा। यदि इसके द्वारा विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर प्राप्त होता है।</p>
	(11)	कुलाधिपति के पास यथानिर्धारित ऐसी अन्य शक्ति होगी।
विश्वविद्यालय के अधिकारीगण	12.	<p>विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :-</p> <p>(1) कुलपति;</p> <p>(2) उप-कुलपति;</p> <p>(3) डीन;</p> <p>(4) कुलसचिव;</p> <p>(5) संविधि द्वारा घोषित किये जाने वाले ऐसे अन्य अधिकारी विश्वविद्यालय के अधिकारी होंगे।</p>

विश्वविद्यालय के कुलपति	13.	<p>(1) कुलपति एक प्रतिष्ठित विद्वान होगा जिसके पास अनुप्रयुक्त विज्ञान, इंजीनियरिंग तथा प्रबंधन के किसी क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर की किसी शिक्षण संस्था का प्रशासनिक अनुभव होगा;</p> <p>(2) कुलपति सरकार की संस्तुति के आधार पर कुलाधिपति द्वारा ऐसी पद्धति में, ऐसी अवधि के लिये और ऐसी परिलब्धियों पर तथा यथानिर्धारित अन्य सेवा शर्तों पर नियुक्त किया जाएगा ।</p> <p>(3) कुलपति विश्वविद्यालय के मुख्य शैक्षणिक एवं कार्यपालक अधिकारी होंगे और विश्वविद्यालय के कृत्यों की देखरेख एवं नियंत्रण करेंगे और विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकारियों के निर्णयों का लागू करेंगे।</p> <p>शर्त यह है कि कोई व्यक्ति जो विश्वविद्यालय का कर्मचारी है वह ऐसी समिति के एक सदस्य के रूप में नामांकित नहीं किया जायेगा ।</p> <p>(4) कुलाधिपति का, यदि उनका यह अभिमत है कि किसी विषय पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई होनी है, तो वह इस अधिनियम द्वारा या अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं और ऐसे विषय पर उसके द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी सूचना ऐसे प्राधिकरण को देंगे;</p> <p>किन्तु यदि संबंधित प्राधिकरण/प्राधिकारी का अभिमत है कि ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिये तो वह विषय को कुलाधिपति को भेज सकता है जिसका इस पर निर्णय अंतिम होगा ।</p> <p>आगे शर्त यह है कि इस उपधारा के अन्तर्गत कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई असंतुष्ट विश्वविद्यालय सेवा के किसी कर्मचारी को उसे सूचित ऐसे कार्रवाई की तिथि से साठ दिन के भीतर बोर्ड के प्रबंधक को ऐसी कार्रवाई के विरुद्ध अपील करने का अधिकार होगा तथा इस पर प्रबंध बोर्ड, कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई की पुष्टि को आशोधित या उलट सकते हैं ।</p> <p>(5) कुलपति संविधि एवं अध्यादेशों द्वारा यथानिर्धारित ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेंगे एवं ऐसे कार्यों का निष्पादन करेंगे ।</p>
विश्वविद्यालय के उप-कुलपति	14.	प्रत्येक उप-कुलपति ऐसी पद्धति, ऐसी परिलब्धियों और अन्य सेवा शर्तों पर नियुक्त किया जायेगा और यथानिर्धारित ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा ।
डीन।	15.	प्रत्येक डीन की नियुक्ति यथानिर्धारित पद्धति से की जायेगी और यथानिर्धारित ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ऐसी कार्यों का निर्वहन करेंगे ।
कुल सचिव।	16.	(1) प्रत्येक कुल सचिव ऐसी पद्धति, ऐसी परिलब्धियों और अन्य सेवा शर्तों पर नियुक्त किया जायेगा और यथानिर्धारित ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा ।

		<p>(2) प्रबंध बोर्ड द्वारा सशक्त किसी पंजीयक के पास विश्वविद्यालय की ओर से समझौते करने तथा हस्ताक्षर करने एवं अभिलेख को प्रमाणित करने का अधिकार होगा ।</p> <p>(3) कुल सचिव अभिलेख के अभिरक्षक के रूप में कार्य करेगा ।</p>
अन्य अधिकारीगण	17.	विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति पद्धति, परिलब्धियाँ, शक्तियाँ और कार्य यथानिर्धारित होंगे ।
विश्वविद्यालय के प्राधिकरण	18.	<p>विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे :-</p> <p>(1) परिषद्;</p> <p>(2) प्रबंध बोर्ड;</p> <p>(3) शैक्षिक परिषद्;</p> <p>(4) योजना बोर्ड;</p> <p>(5) वित्त समिति; तथा</p> <p>(6) परिनियमों द्वारा घोषित किये जा सकने वाले ऐसे अन्य प्राधिकरण विश्वविद्यालय के प्राधिकरण होंगे ।</p>
परिषद् ।	19.	<p>(1) विश्वविद्यालय की परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे:-</p> <p>(i) अध्यक्ष: कुलाधिपति;</p> <p>(ii) कुलपति: (पदेन);</p> <p>(iii) उप-कुलपति (पदेन);</p> <p>(iv) प्रधान सचिव अथवा सचिव, तकनीकी शिक्षा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (पदेन);</p> <p>(v) प्रधान सचिव अथवा सचिव, उच्चतर शिक्षा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (पदेन);</p> <p>(vi) प्रधान सचिव अथवा सचिव, वित्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (पदेन);</p> <p>(vii) कुलाधिपति द्वारा नामित आधारभूत एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन की विधाओं के दो प्रसिद्ध व्यक्ति;</p> <p>(viii) विश्वविद्यालय के समस्त डीन (पदेन),</p> <p>(ix) कुलसचिव (पदेन)- सदस्य सचिव ।</p> <p>(2)(i) पदेन सदस्यों के अतिरिक्त परिषद् के नामित सदस्यों को कार्यकाल पाँच वर्ष होगा ।</p> <p>(ii) जहां पर कोई व्यक्ति पद या नियुक्ति के आधार पर परिषद् का कोई सदस्य बन गया है जब उसका पद या नियुक्ति समाप्त हो जाता/जाती है उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी ।</p>

		<p>(iii) परिषद् का कोई सदस्य उसका सदस्य नहीं बना रहेगा यदि वह त्याग-पत्र देता है या विक्षिप्त मस्तिष्क विकार से ग्रस्त हो जाता है, या दिवालिया हो जाता या नैतिक दुराचरण से जुड़े किसी फौजदारी अपराध के लिये सिद्ध-दोष हो जाता है। कुलपति के अलावा किसी सदस्य की सदस्यता भी समाप्त हो जायेगी यदि वह विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार कर लेता है या यदि वह पदेन सदस्य के रूप में न रहने पर कुलाधिपति की अनुमति लिये बिना परिषद् की लगातार तीन बैठकों में भाग लेने में विफल रहता है।</p> <p>(iv) परिषद् के किसी पदेन सदस्य के अलावा कोई सदस्य कुलाधिपति को सम्बोधित एक पत्र द्वारा अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है और ऐसा त्याग-पत्र, उसके द्वारा स्वीकार होते ही प्रभावी हो जायेगा।</p> <p>(v) परिषद् की कोई भी रिक्ति सम्बद्ध नामांकन करने वाले प्राधिकरण द्वारा नामांकन से भरी जायेगी और रिक्ति की अवधि की समाप्ति पर, ऐसा नामांकन प्रभावी होने के लिये समाप्त होगा।</p>
परिषद् की शक्तियाँ, कर्तव्य और बैठकें।	20.	<p>(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार परिषद् समय-समय पर विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा करेगी तथा विश्वविद्यालय के सुधार और विकास के लिये उपाय सुझायेगी,</p> <p>(2) परिषद् के निम्नलिखित अन्य शक्तियाँ और कार्य होंगे; अर्थात्:-</p> <p>(क) विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक लेखों तथा ऐसे लेखा पर इसके लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन पर विचार करके संकल्प पारित करना;</p> <p>(ख) जो विषय उसके पास परामर्श हेतु भेजा जा सकेगा उस विषय पर चांसलर को परामर्श देना;</p> <p>(ग) यथा निर्धारित ऐसे अन्य कर्तव्यों को निर्वहन।</p> <p>(3)(i) परिषद् की वर्ष में कम से कम एक बैठक होगी। सभा की वार्षिक बैठक तब तक सभापति प्रबंध बोर्ड द्वारा नियत की जाने वाली तिथि को होगी जब तक किसी वर्ष के संबंध में परिषद् द्वारा कोई अन्य तिथि न निश्चित की गई हो तथा जब कुलाधिपति उपस्थित हो, तब सभा की बैठक की अध्यक्षता कुलाधिपति द्वारा की जायेगी;</p> <p>(ii) विश्वविद्यालय की वार्षिक बैठक में परिषद् को कुलपति द्वारा पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट सहित वार्षिक आय तथा व्यय का विवरण, लेखा परीक्षित तुलन-पत्र तथा वित्तीय अनुमान प्रस्तुत किये जायेंगे।</p> <p>(4)(1) परिषद् की बैठक कुलाधिपति द्वारा या कुलपति द्वारा स्वयं बुलाई जायेगी या परिषद् के कम से कम आधे सदस्यों के अनुरोध पर बुलाई जायेगी;</p> <p>(ii) परिषद् की प्रत्येक बैठक के लिये सामान्यतः कम से कम पंद्रह दिन का नोटिस होगा;</p>



		<p>(iii) परिषद् की नामावली सूची में वर्तमान सदस्य के आधे सदस्यों से गणपूर्ति होगी;</p> <p>(iv) प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा और यदि परिषद् द्वारा ज्ञात किये जाने वाले किसी विषय पर बराबर-बराबर मत हो तो इसके अलावा बैठक की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति का निर्णायक मत होगा;</p> <p>(v) यदि सदस्यों के बीच मतभेद है तो बहुमत का मत बना रहेगा; और</p> <p>(vi) यदि परिषद् द्वारा तत्काल कार्रवाई की जानी आवश्यक हो जाती है, तो कुलाधिपति परिषद् के सदस्यों के बीच कागजात परिचालित करके कार्य संचालन की अनुमति दे सकते हैं। इस प्रकार प्रस्तावित कार्रवाई तब तक नहीं की जायेगी जब तक परिषद् के बहुमत द्वारा सहमति न दी गई हो। इस प्रकार की गई कार्रवाई परिषद् के सभी सदस्यों को तत्काल सूचित की जायेगी। यदि सम्बद्ध प्राधिकरण विषय पर निर्णय लेने में विफल रहता है, तो मामला कुलाधिपति को भेजा जायेगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।</p>
प्रबंधन बोर्ड।	21.	<p>(i) प्रबंधन बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक निकाय होगा और इस प्रकार इस अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत बनाई गई संविधि के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय के संचालन के लिये सभी आवश्यक शक्तियां होगी, तथा इस प्रयोजन के लिये अध्यादेशों तथा विनियम बना सकता है तथा इसके नीचे उल्लिखित विषयों के संबंध में भी नियम बना सकता है।</p> <p>(2) प्रबंधन बोर्ड के निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:-</p> <p>(i) सभापति कोई प्रसिद्ध शिक्षाविद् या कोई प्रसिद्ध वैज्ञानिक या कोई प्रसिद्ध इंजीनियर/टैक्नोलॉजिस्ट या कोई उद्योगपति जो निर्धारित पद्धति से कुलाधिपति द्वारा नामित किया जायेगा;</p> <p>(ii) कुलपति (पदेन);</p> <p>(iii) उप-कुलपति (पदेन)।</p> <p>(iv) कुलपति द्वारा प्रस्तुत आठ व्यक्तियों के पैनल में से कुलाधिपति द्वारा नामांकित किए जाने वाले शिक्षा, इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी के प्रयोग क्षेत्र के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक ज्ञान रखने वाले चार व्यक्ति।</p> <p>(v) कुलपति द्वारा नामांकित किए जाने वाले उद्योगों/संगठनों के दो प्रतिनिधि।</p> <p>(vi) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक प्रतिनिधि।</p> <p>(vii) प्रधान सचिव या सचिव, तकनीकी शिक्षा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (पदेन)।</p>

		<p>(viii) प्रधान सचिव या सचिव, वित्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (पदेन)।</p> <p>(ix) प्रधान सचिव या सचिव, उच्च शिक्षा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (पदेन)।</p> <p>(x) रोटेशन आधार पर कुलपति द्वारा नामांकित विश्वविद्यालय के कोई दो संकायाध्यक्ष।</p> <p>(xi) रोटेशन आधार पर कुलपति द्वारा नामांकित विश्वविद्यालय के दो प्राध्यापक।</p> <p>(xii) परिनियम द्वारा यथानिर्धारित ऐसे अन्य-सदस्य।</p> <p>(xiii) कुल-सचिव (पदेन)-सदस्य सचिव।</p> <p>(3) सदस्यों का कार्यकाल और प्रबंधन बोर्ड के सदस्य को देय भत्ते—</p> <p>(i) पदेन सदस्यों के अलावा प्रबंधन बोर्ड के सभापति या किसी अन्य सदस्य का कार्यकाल उसके नामांकन की तिथि से तीन वर्ष होगा, जो दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा;</p> <p>(ii) किसी पदेन सदस्य का कार्यकाल तब तक बना रहेगा जब तक वह पद पर बना रहेगा, जिसके आधार पर वह कोई सदस्य है;</p> <p>(iii) किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नामांकित किसी सदस्य का कार्यकाल, उस सदस्य के शेष काल के लिए बना रहेगा, जिसके स्थान पर वह नियुक्त किया गया है।</p> <p>(4) इस धारा में कुछ भी रहते हुए जाने वाला कोई सदस्य तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसके स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति किसी सदस्य के रूप में नामांकित नहीं किया जाता है।</p> <p>(5) पदेन सदस्यों और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के अलावा प्रबंधन बोर्ड के सदस्य परिनियमों में यथा उपबंधित विश्वविद्यालय से ऐसे भत्ते, यदि कोई हो, पाने के पात्र होंगे।</p>
प्रबंधन बोर्ड की शक्तियां, कर्तव्य और बैठकें	22.	<p>(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रबंधन बोर्ड विश्वविद्यालय के कार्यों की सामान्य देखरेख, निदेशों और नियंत्रण के प्रति उत्तरदायी होगा और इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा अन्यथा न उपबंधित विश्वविद्यालय की सारी शक्तियों का प्रयोग करेगा।</p> <p>(2) उपधारा (1) के उपबंधों की प्रतिकूलता के बिना प्रबंधन बोर्ड की शक्तियां होगी :-</p>

	<p>(i) विश्वविद्यालय के प्रशासन और कार्यप्रणाली से संबंधित नीतिगत मामलों पर निर्णय लेना;</p> <p>(ii) अध्यादेश एवं परिनियम बनाना;</p> <p>(iii) परिषद् द्वारा अपनी वार्षिक बैठक में प्रस्तुत किया जाना;</p> <p>(क) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन, और (ख) वार्षिक लेखे</p> <p>(iv) विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक लेखों और ऐसे लेखों पर उसके लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन पर विचार करना और संकल्प पारित करना;</p> <p>(v) विश्वविद्यालय की सभी वित्तीय शक्तियों का प्रयोग और वित्त, पूंजी निवेश, संपत्तियों, कार्य संव्यवहार, सभी अन्य प्रशासनिक कार्यों का व्यवस्था करना और विनियमित करना और इस प्रयोजन के लिये समितियां गठित करना और ऐसी समितियों या विश्वविद्यालय के ऐसे अधिकारियों को यथोचित शक्तियां सौंपना;</p> <p>(vi) अपनी शक्तियों में से किन्हीं शक्तियों को कुलपति को सौंपना और कुलपति की संस्तुतियों के आधार पर कुल सचिव को, वित्त नियंत्रक या किसी अन्य अधिकारी, कर्मचारी या विश्वविद्यालय के प्राधिकारी को या उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति को शक्तियां सौंपना;</p> <p>(vii) विश्वविद्यालय से संबंधित कोई पूंजी निवेश करना जिनमें अप्रयुक्त आय ऐसे स्टॉक में निधियां, शेयर या प्रतिभूतियां सहित जैसा समय-समय पर उचित समझे या भारत में अचल संपत्ति की खरीद में जिन मामलों में सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक/अपेक्षित है उन मामलों में सरकार की सहायता से अधिग्रहित भूमि या निर्मित भवन को छोड़कर समय-समय पर वित्त समिति की सलाह पर आधारित भिन्न-भिन्न प्रकार के ऐसे निवेश की शक्ति सहित;</p> <p>(viii) विश्वविद्यालय की ओर से संविदा प्राप्त करना, भेद करना कार्यान्वयन करना तथा रद्द करना और इस प्रयोजन के लिये ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करना, जैसा वह उचित समझता हो।</p> <p>(ix) विश्वविद्यालय के कार्य संचालन के लिये आवश्यक भवन, परिसर, फर्नीचर और उपकरण और अन्य साधन उपलब्ध कराना;</p> <p>(x) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों, विद्यार्थियों और कर्मचारियों की किन्हीं शिकायतों के निवारण हेतु शिकायतें प्राप्त करना, यदि वह उचित सझता हो, तो उन पर निर्णय देना;</p> <p>(xi) सभी समूह 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' के पदों का सृजन और विश्वविद्यालय में शैक्षिक तथा अन्य पदों पर नियुक्ति करना और विभिन्न संवर्गों के कर्मचारियों के भर्ती नियम तैयार करना, वेतन संरचना, सेवा शर्तें निर्धारित करना;</p>
--	--

		<p>(xii) परीक्षा शुल्क का निर्धारण करना, परीक्षकों की परिलब्धियां, मानेदय, यात्रा और अन्य भत्तों का निर्धारण;</p> <p>(xiii) विश्वविद्यालय के लिये कॉमन सील का चयन;</p> <p>(xiv) 'स्ववित्त पोषित और समर्थित विद्यार्थियों' के प्रवेशार्थ समय-समय पर उसके द्वारा अधिसूख्या सीटों के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने के लिये नीतिगत दिशा निदेश निर्धारित करना।</p> <p>(xv) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कार्यों का निर्वहन जो इस अधिनियम द्वारा या अन्तर्गत आवश्यक समझे गये या दिये गए हैं।</p> <p>(3)(क) बोर्ड की किसी शैक्षिक वर्ष में कम से कम दो बार बैठक होंगी तथा ऐसी बैठकों के लिये कम से कम पन्द्रह दिन का नोटिस दिया जाएगा।</p> <p>(ख) सभापति के अनुदेशों के अनुसार या बोर्ड के कम से कम आधे सदस्यों के अनुरोध पर कुल सचिव द्वारा बोर्ड की बैठकें बुलाई जाएंगी।</p> <p>(ग) किसी बैठक में बोर्ड के आधे सदस्यों से गणपूर्ति होगी;</p> <p>(घ) यदि सदस्यों के बीच मतभेद है, तो बहुमत का मत बना रहेगा;</p> <p>(ङ) प्रबंध बोर्ड के प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा और यदि प्रबंध बोर्ड द्वारा निर्धारित किये जाने वाले किसी विषय पर बराबर बराबर मत हों, तो इसके अतिरिक्त प्रबंध बोर्ड के अध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य, जैसी भी स्थिति को, का एक निर्णायक मत होगा;</p> <p>(च) प्रबंध बोर्ड की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता सभापति, प्रबंधन बोर्ड द्वारा की जायेगी और उनकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुने गए एक सदस्य द्वारा अध्यक्षता की जायेगी;</p> <p>(छ) यदि प्रबंध बोर्ड द्वारा तत्काल कार्रवाई की जानी आवश्यक हो जाती है, तो सभापति प्रबंध बोर्ड के सदस्यों के बीच कागजात परिचालित करके कार्य संचालन की अनुमति दे सकते हैं। इस प्रकार प्रस्तावित कार्रवाई तब तक नहीं की जायेगी जब तक प्रबंध बोर्ड के बहुमत द्वारा सहमति न दी गई हो। इस प्रकार की गई कार्रवाई प्रबंध बोर्ड के सभी सदस्यों को तत्काल सूचित की जायेगी। यदि सम्बद्ध प्राधिकरण विषय पर निर्णय लेने में विफल रहता है तो मामला चांसलर को भेजा जायेगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।</p>
शैक्षणिक परिषद्	23.	<p>(1) शैक्षिक परिषद्, विश्वविद्यालय की प्रमुख शैक्षिक निकाय होगा और इसका अधिनियम, संविधि और अध्यादेशों के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय के भीतर अनुदेशों, शिक्षा और परीक्षा के मानकों को बनाए रखने के लिये, नियंत्रण होगा, यह विनियमों को बनाने और उसके प्रति उत्तरदायी होगी और संविधि द्वारा उसे प्रदत्त या दी गई/दिये गये ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे अन्य कार्यों का निर्वहन करेगी;</p>

		<p>(2) शैक्षिक परिषद् को सभी शैक्षिक विषयों पर प्रबंध बोर्ड की सलाह देने का अधिकार होगा।</p> <p>(3) शैक्षिक परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—</p> <p>(i) समापति, कुलपति (पदेन);</p> <p>(ii) उप-कुलपति (पदेन);</p> <p>(iii) चार व्यक्ति, जो ख्याति प्राप्त शिक्षाविद्, वैज्ञानिकों या इंजीनियरों में से कुलपति की संस्तुतियों के आधार पर शैक्षिक परिषद् द्वारा सहयोजित किए जाने वाले विश्वविद्यालय के कर्मचारी नहीं हैं।</p> <p>(iv) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नामिती।</p> <p>(v) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का नामिती।</p> <p>(vi) किसी उद्योग संस्था का नामिती, अर्थात् नेस्कॉम, एसोकेम/फिक्की आदि।</p> <p>(vii) विश्वविद्यालय के सभी संकायाध्यक्ष (पदेन)।</p> <p>(viii) सभी विभागाध्यक्ष (पदेन)।</p> <p>(ix) रोटेशन आधार पर कुलपति द्वारा नामांकित किए जाने वाले विश्वविद्यालय का एक प्राध्यापक, एक एसोसिएट प्रोफेसर, एक सहायक प्रोफेसर।</p> <p>(x) परिनियमों द्वारा यथानिर्धारित ऐसे अन्य सदस्य।</p> <p>(xi) कुल सचिव (पदेन)— सदस्य सचिव</p> <p>(4) पदेन सदस्यों के छोड़कर शैक्षिक परिषद् के सदस्य का कार्यकाल तीन वर्ष होगा।</p>
शैक्षणिक परिषद् के अधिकार, प्रकार्य तथा बैठकें	24.(1)	इस अधिनियम के प्रावधानों, संविधि तथा विनियमों तथा प्रबंधन बोर्ड के संपूर्ण पर्यवेक्षण के अंतर्गत विश्वविद्यालय के अकादमिक मामलों तथा अन्य मामलों विशेषतः निम्नलिखित अधिकारों तथा प्रकार्यों का प्रबंधन शैक्षणिक परिषद् करेगी, अर्थात् :-
	(i)	प्रबंधन बोर्ड द्वारा उसे भेजे या सौंपे किसी विषय पर रिपोर्ट देना;
	(ii)	विश्वविद्यालय के अध्यापन पदों के सृजन, समाप्ति या वर्गीकरण तथा देय परिलब्धियों तथा इससे संलग्न कर्तव्यों के विषय में प्रबंध बोर्ड को सिफारिश करना;

	(iii)	विभाग तथा/अथवा केन्द्र (विभाग तथा/अथवा केन्द्र के सृजन सहित) के संगठन के लिए स्कीमें तैयार करना तथा संशोधित या समीक्षा करने तथा इन विभागों का उनके विषय सौंपना तथा प्रबंधन बोर्ड को किसी विभाग की समाप्ति या उप-विभाजन या एक विभाग का दूसरे विभाग से संयोग करने की समीचीनता के बारे में रिपोर्ट देना।
	(iv)	विश्वविद्यालय में नामांकित व्यक्तियों से अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों की शिक्षा तथा परीक्षा की व्यवस्था की सिफारिश करना;
	(v)	विश्वविद्यालय के भीतर अनुसंधान को प्रोत्साहन देना तथा इस अनुसंधान पर समय-समय पर रिपोर्ट मांगना;
	(vi)	शैक्षिक गतिविधियों संबंधी विभागों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों पर विचार करना;
	(vii)	विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए नीतियां निर्धारित करना;
	(viii)	अन्य विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों के डिप्लोमा तथा डिग्रियों को मान्यता देना तथा विश्वविद्यालय के डिप्लोमा तथा डिग्रियों के संदर्भ में उनका मूल्यांकन निर्धारित करना;
	(ix)	प्रबंधन बोर्ड द्वारा स्वीकृति किसी शर्त के अंतर्गत फेलोशिप, छात्रवृत्ति तथा अन्य पुरस्कारों की प्रतियोगिता के समय, पद्धति तथा शर्तों को सुनिश्चित करना तथा इसके निर्णय की सिफारिश करना;
	(x)	परीक्षा के आयोजन की व्यवस्था तथा उन्हें आयोजित करने की तिथि की सिफारिश करना;
	(xi)	विभिन्न परीक्षाओं के परिणामों की घोषणा तथा समीक्षा या इनके लिए समितियाँ या अधिकारी नियुक्त करना तथा उपाधियाँ, सम्मान, डिप्लोमा, लाइसेंस, पद अथवा सम्मान चिह्न प्रदान या भेंट करने संबंधी सिफारिशें करना;
	(xii)	वृत्ति, छात्रवृत्ति, मैडल अथवा पुरस्कारों की सिफारिश करना तथा विनियमों के अनुसार अन्य अवार्ड की सिफारिश करना तथा अवार्डों से संबंधित अन्य शर्तों की सिफारिश करना;
	(xiii)	अध्ययन के निर्धारित पाठ्यक्रमों का पाठ्यचर्या का अनुमोदन या संशोधन तथा पाठ्य पुस्तकों की निर्धारित या संस्तुत सूची का अनुमोदन करना तथा विश्वविद्यालय द्वारा इनका प्रकाशन का निर्णय करना;
	(xiv)	अध्यादेश या विनियमों द्वारा समय-समय पर अपेक्षित फार्मों तथा रजिस्ट्रों का अनुमोदन करना;
	(xv)	समय-समय पर विश्वविद्यालय में पढ़ाए जा रहे पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम तथा विषय वस्तु की रूपरेखा तैयार करने के लिये पालन किए जा रहे शिक्षा के वांछित मानक तैयार करना;

	(xvi)	प्रबंधन बोर्ड को नये पाठ्यक्रमों और वर्तमान पाठ्यक्रम की सीटें बढ़ाने की संस्तुति करना;
	(xvii)	शैक्षणिक विषयों से संबंधित सभी कर्तव्यों का निर्वहण करना तथा इस अधिनियम तथा अध्यादेश तथा उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के प्रावधानों को समुचित रूप से लागू करने के लिए आवश्यक कार्य करना।
	(2)(i)	शैक्षणिक परिषद् जब भी आवश्यक होगा अपनी बैठकें बुलाएगी परन्तु ये बैठकें किसी शैक्षिक वर्ष में दो बार से कम नहीं होंगी;
	(ii)	शैक्षणिक परिषद् के वर्तमान सदस्यों के आधे सदस्यों से अकादमिक परिषद् की किसी बैठक के लिए कोरम बनेगा;
	(iii)	सदस्यों में मत विभिन्नता की स्थिति में बहुमत का निर्णय मान्य होगा;
	(iv)	शैक्षणिक परिषद् का प्रत्येक सदस्य, जिनमें शैक्षणिक परिषद् का अध्यक्ष भी शामिल है, को एक मत देने का अधिकार होगा और यदि शैक्षणिक परिषद् द्वारा किसी प्रश्न के सुनिश्चयन में मतों की संख्या बराबर-बराबर रहती है, तो शैक्षणिक परिषद् के अध्यक्ष या उस बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति के पास एक अतिरिक्त निर्णायक मत होगा;
	(v)	अकादमिक परिषद् की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता कुलपति द्वारा और कुलपति की अनुपस्थिति में सह कुलपति बैठक की अध्यक्षता करेंगे और उनकी अनुपस्थिति में बैठक में चुने किसी सदस्य द्वारा इस अवसर पर अध्यक्षता की जाएगी;
	(vi)	यदि अकादमिक परिषद् द्वारा तत्काल कार्रवाई की जानी आवश्यक हो जाती है तो अकादमिक परिषद् का अध्यक्ष, अकादमिक परिषद् के सदस्यों के बीच दस्तावेजों के परिचालन द्वारा कार्य संचालन की अनुमति दे सकता है। प्रस्तावित कार्रवाई पर जब तक अकादमिक परिषद् के बहुमत सदस्यों की सहमति नहीं होती तब तक प्रस्तावित कार्यवाही नहीं की जायेगी। इसके अनुसरण में की गई कार्रवाई से अकादमिक परिषद् के सभी सदस्यों को तत्काल अवगत कराया जायेगा। यदि संबंधित अधिकारी निर्णय लेने में असमर्थ रहता है, तो विषय को कुलाधिपति को भेजा जायेगा जिसका निर्णय अंतिम होगा;
योजना बोर्ड	25.(1)	विश्वविद्यालय में एक योजना बोर्ड का गठन किया जायेगा जो विश्वविद्यालय की प्रमुख नियोजन निकाय होगा तथा विश्वविद्यालय के विकास के अनुवीक्षण के लिए भी उत्तरदायी होगा;
	(2)	योजना बोर्ड का गठन इसके सदस्यों का कार्यकाल तथा इसके अधिकार तथा प्रकार्य यथानिर्धारित रूप में होंगे।
विभाग	26.(1)	समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा यथा निर्धारित अध्यापन तथा शोध के विभाग होंगे;

	(2)	किसी विभाग के गठन, अधिकार तथा प्रकार्य यथानिर्धारित रूप में होंगे।
वित्त समिति	27.(1)	निम्नलिखित सहित एक वित्त समिति होगी :-
	(i)	अध्यक्ष: अध्यक्ष प्रबंधन बोर्ड (पदेन);
	(ii)	कुलपति: (पदेन);
	(iii)	उप-कुलपति: (पदेन);
	(iv)	लेखा नियंत्रक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार;
	(v)	प्रधान सचिव अथवा सचिव, तकनीकी शिक्षा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (पदेन);
	(vi)	प्रधान सचिव अथवा सचिव, वित्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (पदेन);
	(vii)	कुलपति द्वारा नामित दो संकायाध्यक्ष;
	(viii)	दो विभागाध्यक्ष, वरिष्ठता पर आधारित बारी-बारी से;
	(ix)	प्रबंधन बोर्ड के सदस्यों के बीच में से उसके (प्रबंधन बोर्ड) द्वारा नामित दो अन्य सदस्य जिनमें से कम से कम एक विश्वविद्यालय का कर्मचारी होना चाहिए;
	(x)	परिनियमों द्वारा यथानिर्धारित ऐसे अन्य सदस्य;
	(xi)	कुलसचिव (पदेन)- सदस्य सचिव।
	(2)	पदेन सदस्यों के अलावा वित्त समिति के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा।
	(3)	वित्त समिति के प्रकार्य एवं कर्तव्य निम्न प्रकार होंगे :-
	(क)	विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट की जाँच तथा परीक्षण करना तथा वित्तीय मामलों पर प्रबंधन बोर्ड को सिफारिश करना;
	(ख)	नये खर्चों के लिए प्रस्तावों पर विचार करना तथा प्रबंधन बोर्ड को इसकी सिफारिश करना;
	(ग)	ग्रेडों में संशोधन, वेतनमानों को उन्नत करना और उन मदों संबंधी सारे प्रस्ताव, जो बजट में शामिल नहीं हैं, प्रबंध मंडल द्वारा विचार किए जाने से पूर्व वित्त समिति द्वारा जाँच की जाएगी;



	(घ)	कुल सचिव द्वारा तैयार विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखों तथा वित्तीय अनुमानों पर विचार करना तथा अनुमोदन के लिये वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत करना तथा इसके पश्चात् प्रबन्ध मण्डल को प्रस्तुत करना;
	(ङ)	वित्त समिति विश्वविद्यालय की आय तथा संसाधनों पर आधारित वर्ष के कुल आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय की सीमा निश्चित करेगी और इस प्रकार निश्चित सीमा से अधिक व्यय वित्त समिति के अनुमोदन के बिना विश्वविद्यालय द्वारा खर्च नहीं किया जाएगा;
	(च)	विश्वविद्यालय को प्रभावित करने वाले किसी वित्तीय प्रश्न पर, प्रबंध अपनी तरफ से या प्रबंध बोर्ड द्वारा संदर्भित किए जाने पर प्रबंधन बोर्ड को अपनी राय देना तथा सिफारिश करना;
	(छ)	विश्वविद्यालय से संबंधित किसी धनराशि का निवेश संस्तुत करना जिसमें अप्रयुक्त आय शामिल है, ऐसे स्टॉक, निधियों, शेयरों या प्रतिभूतियों जैसा समय-समय पर उचित समझे या भारत में अचल संपत्ति की खरीद में समय-समय पर ऐसी भिन्न-भिन्न प्रकार के पूंजी निवेश करने की शक्ति सहित।
	(4)	वित्त समिति की बैठक किसी वर्ष में कम से कम चार बार होगी। किसी भी बैठक में वित्त समिति के पाँच सदस्यों का कोरम होगा।
	(5)	सदस्यों में मत-विभिन्नता की स्थिति में उपस्थित सदस्यों का बहुमत बना रहेगा।
अन्य प्राधिकरण	28.	अन्य प्राधिकरणों के गठन, अधिकार तथा प्रकार्य यथानिर्धारित होंगे, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों द्वारा घोषित किए जा सकेंगे।
संविधि	29.	इस अधिनियम, परिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत निम्न सभी या कुछ विषयों पर परिनियम बनाए जा सकते हैं, अर्थात् :-
	(क)	विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों तथा समय-समय पर आवश्यक रूप से गठित किए जाने वाले अन्य निकायों की संरचना, अधिकार तथा प्रकार्य;
	(ख)	प्राधिकरणों तथा विश्वविद्यालय की निकायों का चयन तथा इसके सदस्यों के पद पर बने रहने, सदस्यों की रिक्ति को भरे जाने तथा इससे संबंधित अन्य सभी ऐसे मामले जिनके विषय में विश्वविद्यालय उपबंध बनाना आवश्यक या वाछंनीय समझता है;
	(ग)	विश्वविद्यालय के शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों के सभी वर्ग 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' के नियुक्ति/अनुशासनिक प्राधिकारी;
	(घ)	पूर्व इंदिरा गांधी प्रौद्योगिकी संस्थान में रोजगाररत अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के बने रहने की शर्तें;
	(ङ)	विश्वविद्यालय में अधिकारियों की नियुक्ति की पद्धति तथा उनकी सेवा शर्तें, उनके अधिकार तथा कर्तव्य और सकल परिलब्धियां;

	(च)	विश्वविद्यालय के अध्यापकों, अन्य अकादमिक कर्मचारियों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की पद्धति तथा उनकी परिलब्धियाँ;
	(छ)	किसी अन्य विश्वविद्यालय/उद्योग में कार्यरत शिक्षकों तथा अन्य अकादमिक कर्मचारियों की किसी संयुक्त परियोजना में विनिर्दिष्ट अवधि के लिये कार्य करने के लिये नियुक्ति, उनकी सेवा शर्तें तथा परिलब्धियाँ;
	(ज)	विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त शिक्षकों तथा अकादमिक स्टाफ के अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें;
	(झ)	विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें;
	(ञ)	विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के हित के लिए पेंशन या भविष्य निधि का गठन तथा बीमा स्कीम की स्थापना करना;
	(ट)	विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के वरिष्ठताक्रम का नियंत्रण करने वाले सिद्धान्त;
	(ठ)	विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी या विद्यार्थी द्वारा अपील किए जाने की प्रक्रिया;
	(ड)	मानद उपाधि प्रदान करना;
	(ढ)	फेलोशिप, छात्रवृत्तियाँ, विद्यार्थी वृत्तियाँ, पदक तथा पुरस्कार तथा अन्य प्रोत्साहन प्रारंभ करना;
	(ण)	विश्वविद्यालय के कर्मचारियों में अनुशासन बनाए रखना;
	(त)	चेयरो, विभागों तथा केन्द्रों की स्थापना;
	(थ)	विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित तथा अथवा अनुरक्षित संस्थाओं/केन्द्रों का प्रबंधन, पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण;
	(द)	विश्वविद्यालय के अधिकारियों या प्राधिकरणों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन;
	(ध)	ऐसे सभी विषय जिन पर इस अधिनियम द्वारा या इसके अंतर्गत संविधि द्वारा प्रावधान किया जाना है या किया जा सकता है।
संविधि प्रक्रिया:	30(1)	पहली संविधि, इस अधिनियम के लागू होने से तीस दिन के भीतर कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन से सरकार द्वारा बनाई जाएगी।
	(2)	प्रबंधन बोर्ड समय-समय पर नये या अतिरिक्त संविधि बना सकता है या उपधारा (1) के अंतर्गत इसे संदर्भित संविधि को संशोधित या निरस्त कर सकता है:-

		उपबंध है कि प्रबंधन बोर्ड, तब तक विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण के पद, अधिकार या संरचना को प्रभावित करने वाली किसी संविधि की रचना, संशोधन या निरस्त नहीं करेगा जब तक प्रस्तावित परिवर्तन पर अपनी लिखित राय बताने की पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया जाता तथा अभिव्यक्त राय पर प्रबंधन बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रबंधन बोर्ड द्वारा विचार नहीं कर लिया जाता;
	(3)	प्रत्येक नई संविधि या संविधि में परिवर्धन या इसमें संशोधन अथवा निरसन के लिए कुलाधिपति का अनुमोदन आवश्यक होगा, जो इस पर अपनी सहमति दे सकता है, इसे रोक सकता है या उसके द्वारा दी गई टिप्पणी, यदि कोई है, को देखते हुए प्रबंधन बोर्ड द्वारा पुनर्विचार के लिए वापिस भेज सकता है;
	(4)	किसी नई संविधि या संविधि में संशोधन या किसी वर्तमान संविधि का संशोधन या निरसन तब तक वैध नहीं होगा जब तक कुलाधिपति द्वारा इस पर सहमति प्रदान नहीं की जाती जो इस विषय पर निर्णय लेते समय संबंधित विभाग के दृष्टिकोण पर विचार करेगा।  बशर्ते कि यदि कुलाधिपति प्राप्त संदर्भ के साठ दिनों के भीतर अपना निर्णय सूचित नहीं करता है तो माना जायेगा कि कुलाधिपति ने प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान कर दी है।
अध्यादेश	31(1)	इस अधिनियम तथा संविधियों के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए अध्यादेश लाया जा सकता है; अर्थात् :-
	(क)	विद्यार्थियों का प्रवेश, अध्यापन पाठ्यक्रम तथा उसका शुल्क, डिग्रियों, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र तथा अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं को प्रदान करने संबंधी योग्यताएं तथा फैलोशिप तथा पुरस्कार तथा अन्य ऐसे सम्मान को प्रदान किए जाने की शर्तें;
	(ख)	परीक्षाएं आयोजित करना, जिनमें पद की सेवा शर्तें शामिल है तथा परीक्षकों की नियुक्तियाँ;
	(ग)	विद्यार्थियों के आवास एवं उनके सामान्य अनुशासन की स्थिति;
	(घ)	विश्वविद्यालय द्वारा पोषित महाविद्यालयों एवं संस्थानों का प्रबंधन;
	(ङ)	कर्मचारियों तथा विश्वविद्यालय अथवा विद्यार्थियों एवं विश्वविद्यालय के बीच विवादों के निपटान की पद्धति;
	(च)	कर्मचारियों या विद्यार्थियों के बीच विवादों के निपटान की पद्धति;
	(छ)	किसी खिन्न कर्मचारी या किसी विद्यार्थी द्वारा किसी अपील की पद्धति;
	(ज)	विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के बीच अनुशासन का रखरखाव;
	(झ)	विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के आचरण एवं कार्यों का विनियमन तथा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के आचरण का विनियमन;

	(ज)	कदाचार की श्रेणियों जिसके लिए इस अधिनियम या संविधियों अथवा अध्यादेशों के अधीन कार्रवाई की जाए;
	(ट)	कोई अन्य मामले, जो इस अधिनियम या संविधियों के अधीन या उसके द्वारा है अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किए गए हो या किए जाएं;
	(2)	सरकार के पूर्व अनुमोदन से कुलाधिपति द्वारा प्रथम अध्यादेश तैयार किया जाएगा तथा इस प्रकार तैयार किया गया अध्यादेश यथानिर्धारित पद्धति से प्रबंधन बोर्ड द्वारा किसी भी समय संशोधित, निरसित या परिवर्धित किया जा सकता है।
विनियम।	32.	विश्वविद्यालय के प्राधिकारी तथा उनके द्वारा नियुक्त समिति यदि कोई समिति हो लेकिन इस अधिनियम, संविधि या अध्यादेशों द्वारा उपबंधित नहीं है, इस अधिनियम, संविधि, अध्यादेशों के अनुरूप अपने कार्य व्यवहार के निष्पादन हेतु संविधियों द्वारा यथानिर्धारित पद्धति से विनियम बना सकते हैं।
वार्षिक रिपोर्ट।	33.(1)	विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट प्रबंधन बोर्ड के निर्देशों के अधीन तैयार की जाएगी जिसमें उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विश्वविद्यालय द्वारा किए गए उपाय तथा अन्य मामले सम्मिलित होंगे;
	(2)	इस प्रकार तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट शैक्षणिक वर्ष के समापन से 6 माह के अन्दर कुलाधिपति को प्रस्तुत की जाएगी;
	(3)	उपधारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रति सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी, जो उसे दिल्ली की विधानसभा में यथाशीघ्र प्रस्तुत कराएगी।
वार्षिक लेखें।	34.(1)	विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे तथा तुलन-पत्र कुलाधिपति के निर्देशों के अन्तर्गत तैयार की जाएंगे तथा प्रबंधन बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे तथा प्रत्येक वर्ष कम से कम पन्द्रह महीनों के अन्तराल में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा या इस संबंध में यथाप्राधिकृत व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा लेखा परीक्षा की जाएगी;
	(2)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ लेखों की प्रति कुलाधिपति को प्रबंधन बोर्ड की टिप्पणियों सहित, यदि कोई हो, तो भेजी जाएगी;
	(3)	वार्षिक लेखों पर कुलाधिपति द्वारा की गई कोई टिप्पणी प्रबंधन बोर्ड की सूचना में लाई जाएगी;
	(4)	कुलाधिपति को प्रस्तुत की गई लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखों की प्रति सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी जो कि उसे यथाशीघ्र दिल्ली की विधानसभा में प्रस्तुत कराएगी।
कर्मचारियों की सेवा शर्तें।	35.(1)	विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के नियुक्त प्रत्येक कर्मचारी की नियमित आधार पर या अन्यथा सेवा संविदा का लिखित करार करेगा तथा संविदा की शर्तें इस अधिनियम, संविधि, अध्यादेशों के उपबंधों असंगत नहीं होंगे;

	(2)	उपधारा (1) में उल्लिखित संविदा की एक प्रति विश्वविद्यालय के पास रखी जाएगी तथा उसकी एक प्रति संबंधित कर्मचारी को भी प्रस्तुत की जाएगी।
न्यायाधिकरण मध्यस्थता।	36.	(1) विश्वविद्यालय तथा कर्मचारियों के बीच धारा 35 में उल्लिखित रोजगार संविदा से उत्पन्न कोई विवाद मध्यस्थता न्यायाधिकरण को भेजा जाएगा जिसमें प्रबंधन बोर्ड द्वारा नामित एक सदस्य, संबंधित कर्मचारी द्वारा नामित एक सदस्य तथा कुलाधिपति द्वारा मनोनीत निर्णायक (अम्पायर) सम्मिलित होंगे।  (2) ऐसा प्रत्येक संदर्भ तत्समय प्रवृत्त मध्यस्थता विधि के अर्थ में इस धारा की शर्तों पर मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किया समझा जायेगा तथा उस विधि के समस्त उपबंध उसकी धारा 2 के अपवाद सहित तदनुसार लागू होंगे।  (3) मध्यस्थता न्यायाधिकरण के कार्य को विनियमित करने की पद्धति विश्वविद्यालय द्वारा यथानिर्धारित होगी।  (4) मध्यस्थता न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगा तथा दोनों पक्षों पर बाध्य होगा तथा न्यायाधिकरण द्वारा निर्णित किसी मामले के संबंध में न्यायालय में किसी भी प्रकार का वाद नहीं होगा।
प्रोविडेंट तथा पेंशन निधि।	37.	विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभार्थ ऐसे प्रोविडेंट फण्ड या पेंशन निधि का गठन करेगा या ऐसी बीमा योजनाओं की व्यवस्था करेगा जैसा वह यथा निर्धारित शर्तों एवं पद्धति के अनुसार उचित समझे।  उपबंध है कि वर्तमान कर्मचारियों पर इंदिरा गांधी प्रौद्योगिकी संस्थान में उनकी सेवा पर लागू विद्यमान पेंशन एवं भविष्य निधि स्कीम में चलती रहेंगी।
विश्वविद्यालय प्राधिकारियों एवं निकायों के गठन के बारे में विवाद।	38.	यदि भलीभांति चुने गये या नियुक्त किये गये या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या किसी निकाय में सदस्य के रूप में चुने जाने या नियुक्त किये जाने से संबंधित किसी व्यक्ति के बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, उस स्थिति में मामला प्रबंधन बोर्ड की संस्तुति के साथ कुलाधिपति के पास भेजा जायेगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।
आकस्मिक रिक्तियों को भरना।	39.	विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या किसी अन्य निकाय के सदस्य समस्त आकस्मिक रिक्तियां (पदेन सदस्यों के अतिरिक्त) जब भी सुविधाजनक हो उस व्यक्ति या निकाय द्वारा भरी जायेंगी जो सदस्यों की नियुक्ति, चुनाव करता है या सहभागी बनाता है जिसके स्थान पर रिक्ति हुई है वह उस शेष अवधि के लिये ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य होगा जिसके लिये वह व्यक्ति जिसके स्थान पर उसका चुनाव हुआ है, सदस्य के रूप में रहता।
विश्वविद्यालय प्राधिकारियों या निकायों की कार्यवाही जो रिक्तियों द्वारा अमान्य नहीं है।	40.	किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अमान्य नहीं होगी कि उनके सदस्यों के बीच रिक्ति थी या रिक्तियां थी।

सदभावना पूर्वक की गई कार्यवाही ।	41.	कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी परिषद् में विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी, अधिकारी या कर्मचारी अथवा या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी अथवा अधिकारी या अन्य कर्मचारी के आदेश अथवा निदेश के अधीन कार्य कर रहे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय के विरुद्ध किसी भी ऐसे कार्य के लिए नहीं होगा/होगी जोकि इस अधिनियम या संविधि या अध्यादेशों के उपबंधों के अनुसरण में सदभावनापूर्वक किया गया हो या ऐसा करने का कोई आशय हो ।
विश्वविद्यालय अभिलेख के प्रमाण की पद्धति ।	42.	विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या समिति की किसी प्राप्ति, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्पों की प्रति या विश्वविद्यालय के पास रखे गये अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा भलीभांति बताए किसी रजिस्टर में किसी प्रकार की प्रविष्टि की प्रति यदि इस प्रकार निर्दिष्ट कुल सचिव द्वारा प्रमाणित की गई हो, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 (1872 का 1) या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में निहित किसी बात के अन्यथा होते हुये उसमें विनिर्दिष्ट मामले तथा कार्य व्यवहार को साक्ष्य के रूप में समझा जायेगा जहां उसकी मूल प्रति, यदि प्रस्तुत की गई हो, साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हो ।
कठिनाई दूर करने की शक्ति ।	43.	यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार आदेश द्वारा शासकीय राजपत्र में प्रकाशित, ऐसे उपबंध बना सकती है जो इस अधिनियम के उपबंधों के असंगत न हो, इन कठिनाइयों को दूर करने में आवश्यक या समयोचित प्रतीत होते हों;  बशर्ते कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने के तीन वर्षों की समाप्ति के पश्चात् इस धारा के अधीन ऐसे आदेश नहीं बनाए जाएंगे ।
कार्य संचालन उपबंध ।	44.	इस अधिनियम में तथा संविधियों में किसी बात के अन्यथा होते हुए, —  (क) प्रथम कुलपति तथा प्रथम कुल सचिव कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किये जायेंगे तथा वे संविधियों द्वारा विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों के अनुसार अधिशासित किये जायेंगे;  (ख) प्रथम परिषद् तथा प्रथम प्रबंधन बोर्ड, कुलाधिपति द्वारा सरकार की संस्तुति पर मनोनीत किये जायेंगे एवं तीन वर्षों तक अपने पदों पर बने रहेंगे ।
सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने तथा विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के लिये संविधि तथा अध्यादेश ।	45.	(1) इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित प्रत्येक संविधि तथा अध्यादेश सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किये जायेंगे ।  (2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए प्रत्येक संविधि तथा अध्यादेश के बनने के तुरंत बाद इसे यथाशीघ्र दिल्ली विधानसभा के सत्र के तीस दिनों के अन्दर, चाहे वह एक, दो या इससे अधिक उत्तरवर्ती सत्रों का समाहार हो, सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा उपयुक्त अवधि के अन्तर्गत यदि सदन किसी संविधि या अध्यादेश में किसी प्रकार का संशोधन करने के लिए सहमत होता है या इसके लिए सहमत होता है कि संविधि तथा अध्यादेश नहीं बनाया जाना चाहिए, तो संविधि या अध्यादेश संशोधित रूप में प्रभावी होगा या प्रभावी नहीं होगा, जैसी भी स्थिति हो, तथापि ऐसे संशोधन या निरसन का

		उक्त संविधि तथा अध्यादेश के अन्तर्गत पहले किए गए किसी कार्य की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
मानद डिग्री।	46.	यदि शैक्षणिक परिषद् के सदस्यों के कम से कम दो तिहाई सदस्य यह संस्तुति करते हैं कि किसी व्यक्ति को इस आधार पर मानद डिग्री या शैक्षणिक विशिष्टता प्रदान की जाये जो कि उनके विचार से अत्यधिक ख्याति प्राप्त तथा उत्कृष्ट स्थिति वाला है, ऐसी डिग्री या शैक्षणिक विशिष्टता प्राप्त करने के योग्य है, कुलाधिपति आदेश द्वारा यह निर्णय ले सकता है कि संस्तुति किये गये व्यक्ति को डिग्री प्रदान की जाये।
डिग्री या डिप्लोमा वापस लेना।	47.	<p>(1) प्रबंधन बोर्ड, शैक्षणिक परिषद् की सिफारिश पर तथा कुलाधिपति के अनुमोदन से किसी भी व्यक्ति को प्रदान की गई विशिष्टता, डिग्री, डिप्लोमा या विशेषाधिकार को परिषद् के कुल सदस्यों की बहुमत द्वारा पारित किसी संकल्प द्वारा जोकि उपस्थित परिषद् सदस्यों तथा बैठक के समय मतदान में उपस्थित हों, वापस ले सकता है, यदि ऐसे व्यक्ति को न्यायालय किसी अपराध के लिये सिद्ध दोषी माना गया हो जो कि प्रबंधन बोर्ड के विचार से कदाचार में लिप्त हो या यदि वह गंभीर दुराचरण का दोषी पाया गया है।</p> <p>(2) उपधारा (1) के अधीन कोई कार्रवाई तब तक किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं की जायेगी जब तक उसे की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध सुनवाई एवं कारण बताने का उचित अवसर न दिया गया हो।</p> <p>(3) प्रबंधन बोर्ड द्वारा पारित संकल्प की प्रति संबंधित व्यक्ति को तुरन्त भेजी जायेगी।</p> <p>(4) प्रबंधन बोर्ड द्वारा दिये गये निर्णयों से खिन्न कोई व्यक्ति ऐसे संकल्प की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के अंदर कुलाधिपति को अपील कर सकता है।</p> <p>(5) ऐसी अपील में कुलाधिपति का निर्णय अंतिम होगा।</p>
अनुशासन।	48.	<p>(1) विश्वविद्यालय अपने प्रोक्ट्रीयल बोर्ड के माध्यम से विद्यार्थियों में कठोर अनुशासन बनाएगा। इस कार्य के लिये कुलपति द्वारा प्रोफेसर/एसोप्रोफेसर के पद के संकाय सदस्य को प्रोक्टर नियुक्त किया जायेगा जो अपने पद पर दो वर्ष के लिये कार्य करेगा।</p> <p>(2) प्रोक्ट्रीयल बोर्ड विद्यार्थियों के अनुशासन संबंधी सभी मामलों को देखेगा तथा कुलपति विश्वविद्यालय से बर्खास्तगी सहित अन्य दंड देने के लिये अंतिम प्राधिकारी होगा।</p>
नियुक्तियों की मान्य वैधता।	49.	किसी अन्य कानून या तत्समय प्रचलित विधि के प्रवृत्त रखने वाले दस्तावेज में कुछ भी रहते हुए, विश्वविद्यालय में संविधियों अध्यादेश तथा विनियमों के अनुसार किसी पद पर की गई नियुक्तियां वैध मानी जाएंगी और कानून के अनुसार होगी।

ओवरराइडिंग प्रभाव।	50.	इस अधिनियम तथा उसके अधीन निर्मित अध्यादेश, संविधियों एवं विनियमों के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी विधि किसी अन्य विधि या दस्तावेज में निहित किसी बात के असंगत होते हुये प्रभावी नहीं होंगे।
प्रायोजित योजनायें।	51.	जब भी विश्वविद्यालय सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या किसी एजेंसी द्वारा प्रायोजित विश्वविद्यालय द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली किसी स्कीम से निधि प्राप्त करता है तो इस अधिनियम या संविधि या अध्यादेश में किसी बात के अन्यथा रहते हुये:—  (क) प्राप्त राशि विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय निधि से अलग रखी जायेगी तथा केवल योजना के उद्देश्य हेतु प्रयुक्त की जायेगी, तथा  (ख) योजना निष्पादित करने के लिये अपेक्षित स्टाफ समर्थित संगठन द्वारा निबंधित शर्तों के अनुसार भर्ती किया जायेगा।
निदेश देने का अधिकार	52.	कुलाधिपति स्वतः या प्रबंध बोर्ड की सिफारिश पर विश्वविद्यालय की प्रशासनिक, वित्तीय या शैक्षणिक हितों और विशेषतः विश्वविद्यालय में शान्ति एवं सौहार्द बनाए रखने तथा विश्वविद्यालय की संपत्ति के संरक्षण के लिए यथावश्यक या यथोचित निदेश जारी कर सकता है।

F. No. 14(16)/LA-2011/Cons2law/98.—The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on 11th July, 2012 and is hereby published for general information :—

**“THE INDIRA GANDHI DELHI TECHNICAL UNIVERSITY FOR WOMEN ACT, 2012  
(DELHI ACT 09 OF 2012)**

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 31<sup>st</sup> May, 2012)

[ 11<sup>th</sup> July, 2012]

An Act to provide for the reconstitution of the Indira Gandhi Institute of Technology as Indira Gandhi Delhi Technical University for Women and to incorporate it as a non-affiliating teaching and research University at Delhi to facilitate and promote studies, research, technology, innovation, incubation and extension work in emerging areas of professional education with focus on engineering, technology, applied sciences, management and its allied areas and also to achieve excellence in these and related fields and other matters connected therewith or incidental thereto.

Whereas, the Indira Gandhi Institute of Technology is a constituent college of Guru Gobind Singh Indraprastha University of the Government of National Capital Territory of Delhi;

And whereas, it is expedient to confer on the said institution the status of a University to enable it to function more efficiently as a teaching and research centre in various branches of learning and courses of study promoting advancement and dissemination of knowledge and learning, and to meet the requirement of higher education and research in the field of engineering and technology, applied sciences and management sciences etc., foster industry relevant research and innovations and to avail better scopes and opportunities to serve the society and the nation.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:—



1. **Short title and commencement-** (1) This act may be called the **Indira Gandhi Delhi Technical University for Women Act, 2012.**
- (2) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the official Gazette, appoint.
2. **Definitions-** In this Act, unless the context otherwise requires, -
  - (a) "Academic Council" means the Academic Council of the University;
  - (b) "Academic Staff" means such categories of staff as are designated by the Statutes to be the academic staff of the University;
  - (c) "Board of Management" means the Board of Management of the University;
  - (d) "campus" means the unit established or constituted by the University for making arrangements for instruction, or research, or both;
  - (e) "Chancellor", "Vice Chancellor" and "Pro Vice-Chancellors" mean respectively, the Chancellor, the Vice Chancellor and the Pro Vice-Chancellor of the University;
  - (f) "Centre" means Centre of excellence in a specified academic speciality or area established or maintained by University;
  - (g) "Court" means the Court of the University;
  - (h) "Delhi" means the National Capital Territory of Delhi;
  - (i) "Department" means a Department of studies of the University;
  - (j) "employee" means any person appointed by the University;
  - (k) "Finance Committee" means the Finance Committee of the University;
  - (l) "Government" means the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi appointed by the President under article 239 and designated as such under article 239AA of the Constitution of India;
  - (m) "Hall" means a unit of residence or of corporate life for the students of the University;
  - (n) "Institution" means any institution established or maintained by the University;
  - (o) "Lieutenant Governor" means the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi appointed by the President under article 239 and designated as such under article 239AA of the Constitution of India;
  - (p) "misconduct" means a misconduct prescribed by the Statutes and the Ordinance;
  - (q) "notification" means a notification published in the official Gazette;
  - (r) "Planning Board" means the Planning Board of the University;
  - (s) "prescribed" means prescribed by the Statutes or Ordinances or Regulations, as the case may be, made under this Act;
  - (t) "Registrar" means the Registrar of the University;
  - (u) "Statutes", "Ordinances" and "Regulations" mean respectively the Statutes, Ordinances and Regulations of the University for the time being in force;

- (v) "University" means the Indira Gandhi Delhi Technical University for Women as incorporated under this Act; and
- (w) "University teachers" means Professors, Associate Professors and Assistant Professors appointed for imparting instruction or conducting research in the University and are designated as teachers by the Statutes.

3. **Incorporation of the University** - (1) With effect from such date as the Government may, by notification in the official Gazette, appoint, there shall be established a University by the name of "Indira Gandhi Delhi Technical University for Women", comprising the Chancellor, the Vice Chancellor, the Pro-Vice Chancellor, the first members of the Court, the Board of Management and the Academic Council of the University and all such persons as may hereafter be appointed to such office or as members so long as they continue to hold such office or membership.

- (2) The University shall be a body corporate with the name aforesaid having perpetual succession and a common seal with power, subject to the provisions of this Act, to acquire, hold and dispose of property and to contract, and may by the said name sue or be sued.
- (3) The University shall be a Centre for excellence engaged in teaching and research in emerging areas of professional education with focus on but not restricted to Engineering, Technology, Applied Sciences and Management and shall promote inter-disciplinary education and research to achieve excellence in these and related fields.
- (4) The University shall be administratively autonomous and shall receive grant-in-aid from Government of Delhi to provide education to the girls' students and as such shall receive funds for capital and operational expenditure from Government of Delhi, having its own governance as well as administrative policies and practices as prescribed.
- (5) The University shall initially function from the Kashmere Gate Campus. An appropriate piece of land shall be provided by the Government to the University. The Government shall initially extend funds for the establishment of infrastructure including land development, architectural design, buildings, equipment and other needs.

4. **Effect of incorporation of University** - On and from the commencement of this Act-

- (a) any reference to the Indira Gandhi Institute of Technology in any law (other than this Act) or in any contract or other instrument shall be deemed as a reference to the University;
- (b) all the property, movable or immovable, of or belonging to the Indira Gandhi Institute of Technology shall vest in the University;
- (c) all the rights and liabilities of the Indira Gandhi Institute of Technology shall be transferred to and be the rights and liabilities of the University;
- (d) every person employed by the Indira Gandhi Institute of Technology immediately before such commencement shall hold his office or service in the University by the same tenure,

at the same remuneration and upon the same terms and conditions and with the same rights and privileges as to pension, leave, gratuity, provident fund and other matters including all service related matters with regard to promotion and disciplinary actions as he would have held the same if this Act had not been passed, and shall continue to do so unless and until his employment is terminated or he has opted for the University's terms and conditions of employment which would be uniform for the same class of employees; and

- (e) notwithstanding anything contained in this Act, existing students of the Indira Gandhi Institute of Technology, who would have been admitted before the establishment of the University under section 3 of this Act, shall continue to pursue their academic courses and programmes of study under the enrolment and affiliation of the Guru Gobind Singh Indraprastha University, New Delhi, which shall conduct examinations to them and award degrees to them upon successful completion of the courses and programmes of study they are pursuing there at presently.
- (f) The expenditure out of grant-in-aid shall be incurred by the University in accordance with the pattern of aid approved by the Government, provision of GFR, 2005 as amended from time to time and instructions / guidelines / directives issued by the Govt. of NCT of Delhi. They shall follow financial rules of discipline as applicable in Govt. until and unless they frame rules of their own, approved by Government.

**5 Jurisdiction** - Save as otherwise provided by or under this Act, the limits of the area within which the University shall exercise its powers, shall be those of the National Capital Territory of Delhi.

**6. Objects of the University** - The objects of the University shall be-

- (1) to evolve and impart comprehensive professional education with focus on but not restricted to Engineering, Technology, Sciences, Management and such areas as deemed fit;
- (2) to facilitate and promote studies leading to award of degrees, diplomas and certificates;
- (3) to achieve excellence in Engineering, Technology, Sciences, Management and allied areas and matters connected therewith or incidental thereto;
- (4) to establish Centres of Advanced Studies, Research and innovation in various relevant areas of Sciences, Engineering, Technology, Management and allied areas;
- (5) to promote development of products, services and entrepreneurship;
- (6) to be industry relevant and to create an impact on the academic community in India and abroad;
- (7) to establish linkages between the University, Industries, Research and Development Organizations and other Universities/ Institutes for collaborative (including dual degree) teaching and research programmes in India and abroad;
- (8) to promote global interaction through faculty and student exchange in the areas of Science, Engineering, Technology, Management and other allied areas as deemed fit;
- (9) to set up innovation centres, knowledge Park and Technology incubators to foster Techno-entrepreneurship, innovation and new product development;

- (10) to disseminate knowledge and contribute towards nation building and faculty development by organizing expert lectures, seminars, symposia, workshops, conferences, summer and winter schools, short term training programs and refresher courses from time to time;
- (11) to promote and foster cultural and ethical values with a view to promote and foster professional morality, research integrity, globally acceptable business ethics and morals for professionals;
- (12) to publish periodicals, treatises, studies, books, reports, journals and other literatures on subjects pertinent to academic areas of the university, including electronic resources;
- (13) to undertake study, training projects and technology transfer programmes relating to Science, Engineering, Technology and Management;
- (14) to do all such things as are incidental, necessary or conducive to the attainment of all or any of the objectives of the University.

**7. Powers and functions of the University** - The University shall have the following powers and perform the following functions namely:-

- (i) to provide for instruction in such branches of learning as the University may, from time to time, determine and to make provisions for research and for the advancement and dissemination of knowledge and skills;
- (ii) to hold examination and to grant, degrees, diplomas and certificates subject to such conditions as the University may determine and to confer degrees and other academic distinctions or titles from time to time on the basis of examinations, evaluation or any other method of testing, on persons and withdraw any such award for good and sufficient reasons;
- (iii) to confer honorary degrees or other distinctions;
- (iv) to organize and to undertake extra-mural studies and extension services;
- (v) to create teaching, research, administrative, technical, ministerial and other posts under the University and to make appointments thereto in accordance with provisions as prescribed;
- (vi) to recognize persons as professors, associate professors or assistant professors as teachers of the University;
- (vii) to provide for the terms and conditions of service of teachers and other members of the academic or administrative staff appointed by the University;
- (viii) to co-operate or collaborate or associate with any other university, authority or institution of higher learning, research laboratory, industry in such manner and for such purpose as the University may determine;

- (ix) to establish centres for education and research at all levels (undergraduate, postgraduate and research) with accredited and reputed foreign Universities in Sciences, Engineering, Technology and Management and in any other subjects as deemed fit;
- (x) to prescribe for supernumerary seats, over and above the approved intake, across different disciplines and programs for the foreign students, the persons of Indian origin (PIOs), the Non-Resident Indians (NRIs) and the Self-financing and Sponsored students at a fee to be decided by it from time to time;
- (xi) to appoint persons working in any other university or organizations as teachers of the University for a specified period;
- (xii) to build up a body of academia to perform academic functions, and to pay them remuneration in the manner prescribed;
- (xiii) to enable the co-operation and promote collaboration with institutions in India and abroad for imparting instructions or supervising research, or both;
- (xiv) to establish, maintain institutions, campuses and such other centers of education, research, training and extension as deemed appropriate by the University;
- (xv) to set up central facilities like computer centre, instrumentation centre, central workshop, central library, auditorium, etc;
- (xvi) to set up curriculum development cells for different subjects to create a repository of learning material in print and electronic forms;
- (xvii) to make provision for research and consultancy services and, for that purpose, to enter into such arrangements with other institutions or bodies as the University may deem fit;
- (xviii) to determine mode and standards for admissions to the University which may include examinations, evaluation or any other method of selection;
- (xix) to institute and award fellowships, scholarships, studentship, medals and prizes;
- (xx) to prescribe, demand and receive payment of fees and other charges;
- (xxi) to establish, maintain and manage halls, hostels, residences etc. for the faculty, staff, students and scholars;
- (xxii) to prescribe, supervise, and regulate the residence of students of the University;
- (xxiii) to prescribe and regulate the conduct of students and enforce discipline amongst the students of the University and to make arrangements for promoting their health, welfare and cultural and corporate life;
- (xxiv) to prescribe a code of ethics, code of conduct and disciplinary rules for its employees and Code of Discipline for the students;
- (xxv) to regulate the work and conduct of employees of the University and take such disciplinary measures in this regard as may deem necessary;

- (xxvi) to make arrangements for promoting the health and general welfare of employees of the University;
- (xxvii) to create a corpus fund for the University and transfer, in full or part, donations received from alumni, industries and other national and international foundations, organizations as may be approved by the Board of Management of the University and to decide the modalities for the utilization of such a corpus fund;
- (xxviii) to receive benefactions, donations and gifts from persons and to name after them such chairs, institutions, buildings and the like as the University may determine, whose gift or donation to the University is worth such amount as the University may decide;
- (xxix) to acquire by gift, purchase, lease, hire or otherwise, howsoever, any movable or immovable property which may be necessary or convenient for the purpose of the University and to build, construct, improve, alter, demolish, repair and maintain such buildings, works and constructions as may be necessary for carrying out the objects of the University;
- (xxx) to sell, lease, exchange, hire or otherwise transfer all or any portion of the movable and immovable properties of the University, provided that prior approval in writing of the Government is obtained for the transfer or disposal of the same;
- (xxxi) to borrow, with the approval of the Government, on security of the property of the University, moneys for the purpose of the University;
- (xxxii) to assess the needs in terms of subjects, fields of specialization, levels of education and training of technical and other manpower, both on short and long term basis, and to initiate necessary programmes to meet those needs;
- (xxxiii) to initiate measures to enlist the cooperation of the industry and other expert agencies to provide complementary facilities;
- (xxxiv) to provide for instruction through "distance learning" and "open approach" and for mobility of students from the non-formal or open learning stream to the formal stream and vice versa;
- (xxxv) to make appointment in Emeritus capacity of eminent employees who have rendered distinguished service on such terms and conditions as may be prescribed; and
- (xxxvi) to do all such other acts and things as may be necessary or incidental to the exercise of all or any of the powers of the University or necessary for or conducive to the attainment of all or any of the objects of the University.

8. **University open to all classes, castes and creed -** (a) **Students -** (1) The University shall be open to only the persons of female gender to be admitted as students to the University, or to graduate thereat, and it shall not be lawful for the University to adopt or impose on any person any test whatsoever of religious belief or profession or political opinion in order to entitle her to be admitted as a student of the University;

- (2) Nothing in this section shall be deemed to prevent the University from making any special provision for the admission as women students belonging to the weaker sections of the Society, and in particular, of women belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes;
- (3) The University shall be open to female students of any nationality and those may be admitted in the manner so prescribed.
- (b) **Employees** - (1) The University shall be open to persons of either sex or whatever race, creed, caste or class, and it shall not be lawful for the University to adopt or impose on any person any test whatsoever of religious belief or profession or political opinion in order to entitle him/her to be appointed as a teacher of the University or to hold any other office therein or to enjoy or exercise any privilege thereof.
- (2) Nothing in this section shall be deemed to prevent the University from making any special provision for the appointment of persons belonging to the weaker sections of the Society, and in particular, of persons belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes;
9. **Teaching in the University** - (1) The teaching in connection with the degree, diploma and certificate programmes of the University shall be conducted in accordance with the Ordinances and Regulations.
- (2) The courses and Curricula and the authorities responsible for organizing the teaching of such courses and curricula shall be as prescribed by the Ordinances.
10. **Visitor of the University** - (1) The President of the Republic of India shall be the Visitor of the University.
- (2) Any dispute arising between the University and any other university established by law in Delhi may be referred to the Visitor whose decision shall be final and binding on the parties.
11. **Chancellor of the University** - (1) The Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi shall be the Chancellor of the University.
- (2) The Chancellor shall, if present, preside over the convocation of the University for conferring degrees.
- (3) The Chancellor shall have the right to cause an inspection, to be made by such person or persons as he may direct, of the University, an Institute/Center maintained by the University, its buildings, laboratories and equipment, and also of the examination, teaching and other work conducted or done by the University, or to cause an inquiry

to be made in the like manner in respect of all or any of the matters connected with the University.

- (4) The Chancellor shall, in every case, give notice to the University of his intention to cause an inspection or inquiry to be made and the University shall, on receipt of such notice, have the right to make such representation to the Chancellor, as it may consider necessary, within such period as specified in the notice.
- (5) After considering the representation, if any, made by the University, the Chancellor may cause such inspection or inquiry as is referred to in sub-section (3).
- (6) In case, an inspection or inquiry has been caused to be made by the Chancellor, the University shall be entitled to appoint a representative who shall have the right to be present and be heard at such inspection or inquiry.
- (7) The Chancellor may address the Vice-Chancellor with reference to the result of such inspection or inquiry as is referred to in sub-section (3) and the Vice-Chancellor shall communicate to the Board of Management the views of the Chancellor with such advice as the Chancellor may be pleased to offer upon the action to be taken thereon.
- (8) The Board of Management shall communicate through the Vice-Chancellor to the Chancellor such action, if any, as he proposes to take or has been taken by him upon the result of such inspection or inquiry.
- (9) In case, the Board of Management does not, within a reasonable time, take action to the satisfaction of the Chancellor, the Chancellor may issue such directions as he may think fit and the Board of Management shall comply with such directions.
- (10) Without prejudice to the foregoing provisions of this section, the Chancellor may, by order in writing, annul any proceeding of the University which is not in conformity with this Act, the Statutes or the Ordinances:

Provided that before making any such order, the Chancellor shall call upon the University to show cause why such an order should not be made and shall consider the cause shown, if any, within the time-limit specified by him.

- (11) The Chancellor shall have such other powers as may be prescribed.

**12. Officers of the University** - The following shall be the Officers of the University:-

- (1) the Vice-Chancellor;
- (2) the Pro Vice-Chancellor;
- (3) the Deans;
- (4) the Registrar;
- (5) such other officers as may be declared by the Statutes to be the Officers of the University.



IV]

- 13. Vice-Chancellor of the University -** (1) The Vice-Chancellor shall be a scholar of eminence in one of the areas of engineering, technology, management and allied areas, pertinent to the University and having rich administrative and academic experience in Institution of higher learning.
- (2) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor, in such manner, for such term and on such emoluments and other conditions of service as may be prescribed.
- (3) The Vice-Chancellor shall be the principal academic and executive officer of the University and shall exercise supervision and control over the affairs of the University, give effect to the decisions of all the authorities of the University and shall be responsible for maintenance of discipline therein.
- (4) The Vice-Chancellor may, if he is of the opinion that immediate action is necessary on any matter, exercise any power conferred on any authority of the University by or under this Act and shall report to such authority the action taken by him on such matter:
- Provided that if the authority concerned is of the opinion that such action ought not to have been taken, the Chancellor shall take such action as is necessary and feasible to annul the action taken by the Vice-Chancellor in excess of the powers conferred upon him:
- Provided further that any person in the service of the University who is aggrieved by the action taken by the Vice-Chancellor under this sub-section, shall, have the right to appeal against such action to the Board of Management within sixty days from the date on which such action is communicated to him and thereupon the Board of Management may confirm, modify or reverse the action taken by the Vice-Chancellor
- (5) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers and perform such other functions as may be prescribed by the Statutes and the Ordinances.
- 14. Pro Vice-Chancellors of the University -** Every Pro Vice-Chancellor shall be appointed in such manner, on such emoluments and other conditions of service, and shall exercise such powers and perform such functions, as may be prescribed.
- 15. The Deans -** Every Dean shall be appointed in such manner, and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed.
- 16. The Registrar -** (1) Registrar shall be appointed in such a manner, on such emoluments and other conditions of service, and shall exercise such powers and perform such functions, as may be prescribed.

- (2) A Registrar empowered by the Board of Management shall have the power to enter into, and sign agreements and authenticate records on behalf of the University.
- (3) The Registrar shall act as the custodian of records.
17. **Other Officers** - The manner of appointment, emoluments, powers and duties of the other officers of the University shall be such as may be prescribed.
18. **Authorities of the University** - The following shall be the authorities of the University -
- (1) The Court;
  - (2) The Board of Management;
  - (3) The Academic Council;
  - (4) The Planning Board;
  - (5) The Finance Committee; and
  - (6) Such other authorities as may be declared by the Statutes to be the authorities of the University.
19. **The Court** - (1) The Court of the University shall consist of the following members:
- (i) Chairperson: Chancellor;
  - (ii) Vice-Chancellor (Ex-officio);
  - (iii) Pro Vice-Chancellor (Ex-officio);
  - (iv) Principal Secretary or Secretary, Technical Education, Govt. of NCT of Delhi (Ex-officio);
  - (v) Principal Secretary or Secretary, Higher Education, Govt. of NCT of Delhi (Ex-officio);
  - (vi) Principal Secretary or Secretary, Finance, Govt. of NCT of Delhi (Ex-officio);
  - (vii) Two eminent persons in the disciplines of basic and applied sciences, Engineering Technology and Management, nominated by the Chancellor;
  - (viii) All Deans of the University (Ex-officio);
  - (ix) Registrar (Ex-officio) - Member Secretary.
- (2) (i) The term of office of the nominated members of the Court, other than ex-officio members, shall be five years.

- (ii) Where a person has become a member of Court by reason of the office or appointment he holds, his membership shall terminate when he ceases to hold that office or appointment;
- (iii) A member of the Court shall cease to be a member if he resigns or becomes of unsound mind, or becomes insolvent or is convicted of a criminal offence involving moral turpitude. A member, other than the nominated member, shall also cease to be member if he accepts a full time appointment in another University; or if he not being an Ex-officio member fails to attend three consecutive meetings of the Court without the leave of the Chancellor;
- (iv) A member of the Court, other than an ex-officio member, may resign his office by a letter addressed to the Chancellor and such resignation shall take effect as soon as it has been accepted by him;
- (v) Any vacancy in the Court shall be filled by nomination by the respective nominating authority and on expiry of the period of the vacancy such nomination shall cease to be effective.

20. **Powers, functions and meetings of the Court** – (1) Subject to the provisions of this Act, the Court shall review, from time to time, the broad policies and programmes of the University and suggest measures for improvement and development of the University.

(2) The Court shall have the following other powers and functions namely:-

- (a) to consider and pass resolutions on the annual report and the annual accounts of the University and the report of its auditors on such accounts;
- (b) to advise the Chancellor in respect of any matter which may be referred to it for advice;
- (c) to perform such other functions as may be prescribed.

(3) (i) The Court shall meet at least once in a year. An annual meeting of the Court shall be held on the date to be fixed by the Chairman, Board of Management, unless some other date has been fixed by the Court in respect of any year and meeting of the Court shall be presided over by the Chancellor when he is present;

(ii) The Annual Report of the University during the previous year, together with annual accounts, the balance sheet as audited, shall be presented by the Vice-Chancellor to the Court at its annual meeting

(4) (i) Meeting of the Court shall be called by the Chancellor or by the Vice-Chancellor either on his own or at the request of not less than half the members of the court.

- (ii) For every meeting of the Court, normally fifteen days notice shall be given
- (iii) One half of the members existing on the rolls of the Court shall form the quorum;
- (iv) Each member shall have one vote and if there be equality of votes on any question to be determined by the Court, the person presiding over the meeting shall, in addition, have a casting vote.
- (v) In case of difference of opinion among the members, the opinion of the majority shall prevail.
- (vi) If urgent action by the Court becomes necessary, the Chancellor may permit the business to be transacted by circulation of papers to the members of the Court. The action so proposed to be taken shall not be taken unless agreed to by a majority of the members of the Court. The action so taken shall be forthwith intimated to all the members of the Court. In case the authority concerned fails to take a decision the matter shall be referred to the Chancellor, whose decision shall be final

**21. The Board of Management -** (1) The Board of Management shall be the principal executive authority of the University and as such shall have all powers necessary to administer the University subject to the provisions of this Act and the Statutes made there under, and may make ordinances and regulations for that purpose and also with respect to matters provided hereunder.

(2) The Board of Management shall consist of the following persons, namely:

- (i) Chairperson shall be an eminent educationist or an eminent scientist or an eminent engineer/technologist or an eminent industrialist to be nominated by the Chancellor in the manner prescribed;
- (ii) Vice-Chancellor (Ex-officio);
- (iii) Pro Vice-Chancellor (Ex-officio);
- (iv) Four persons having special knowledge or practical experience in respect of education, Engineering and Technology, domain of application of technology, to be nominated by the Chancellor, from a panel of eight persons submitted by the Vice-Chancellor.
- (v) Two representatives of the Industries/ Organizations, to be nominated by the Vice-Chancellor;
- (vi) A representative of University Grants Commission (UGC);
- (vii) Principal Secretary or Secretary, Technical Education, Govt. of NCT of Delhi (Ex-officio);  
Principal Secretary or Secretary, Finance, Govt. of NCT of Delhi (Ex-officio);

- (ix) Principal Secretary or Secretary, Higher Education, Govt. of NCT of Delhi (Ex-officio);
  - (x) Any two Deans of the University nominated by Vice-Chancellor on rotation basis;
  - (xi) Two Professors of the University nominated by Vice-Chancellor on rotation basis;
  - (xii) Such other members as may be prescribed by the statute
  - (xiii) The Registrar (ex-officio) - Member-Secretary
- (3) Term of office of members and allowances payable to, the member of the Board of Management -
- (i) The term of office of the Chairperson or, any other member of the Board of Management, other than ex-officio members, shall be three years from the date of his nomination, extendable by two years;
  - (ii) the term of office of an ex-officio member shall continue so long as he holds the office by virtue of which he is a member;
  - (iii) the term of office of a member nominated to fill a casual vacancy shall continue for the remainder of the term of the member in whose place he has been nominated
- (4) Notwithstanding anything contained in this section, an out-going member shall, continue in office until another person is nominated as a member in his place.
- (5) The members of the Board of Management other than ex-officio members and the University employees shall be entitled to such allowances, if any, from the University as may be provided for in the Statutes.
22. **Powers, functions and meetings of the Board of Management** - (1) Subject to the provisions of this Act, the Board of Management shall be responsible for the general superintendence, directions and control of the affairs of the University and shall exercise all the powers of the University not otherwise provided for by this Act, the Statutes and the Ordinances.
- (2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), the Board of Management shall have the powers -
- (i) to take decisions on questions of policy relating to the administration and working of the University;
  - (ii) to make ordinances and statutes;
  - (iii) to present to the Court at its annual meeting:
    - (a) annual report of the University; and
    - (b) annual accounts

- (iv) to consider and pass resolutions on the annual report and the annual accounts of the University and the reports of its auditors on such accounts;
  - (v) to exercise all financial powers and manage and regulate the finances, accounts, investment, properties, business and all other administrative affairs of the University and for the purpose, constitute committees and delegate the powers to such committees or such officers of the University as it may deem fit;
  - (vi) to delegate any of its powers to the Vice-Chancellor, and on the recommendations of the Vice-Chancellor to the Registrar, the Controller of Finance or any other officer, employee or authority of the University or to a committee appointed by it;
  - (vii) to invest any money belonging to the University, including any unapplied income, in such stock, funds, shares or securities as it may, from time to time, think fit, or in the purchase or immovable property in India, with the like power of varying such investments from time to time based on the advice of the Finance Committee; except land acquired or buildings constructed with the assistance of the Government, in which cases, the prior approval of the Government shall be required;
  - (viii) to enter into, vary, carryout and cancel contracts on behalf of the University and for that purpose to appoint such officers as it may think fit;
  - (ix) to provide the buildings, premises, furniture and apparatus and other means needed for carrying on the work of the University;
  - (x) to entertain, adjudicate upon, and if it thinks fit, to redress any grievances of the officers, the teachers, the students and the employees of the University;
  - (xi) to create all Groups A, B, C, & D posts and appoint persons to academic as well as other posts in the University and to frame recruitment rules and determine salary structure and terms and conditions of different cadres of employees;
  - (xii) to fix the examination fee; emoluments, honorarium and traveling and other allowances of the examiners;
  - (xiii) to select a common seal for the University;
  - (xiv) to lay down policy guidelines for admitting "self financing and sponsored students" as supernumerary against higher fee prescribed by it from time to time;
  - (xv) to exercise such other powers and to perform such other duties as may be considered necessary or imposed on it by or under this Act.
- (3) (a) The Board shall meet at least, two times in an academic year and not less than fifteen days notice shall be given for such meetings;
- (b) The meetings of the Board shall be called by the Registrar under instructions of the Chairperson or at the request of not less than half members of the Board;

- (c) One half of the members of the Board shall form the quorum at any meeting;
  - (d) In case of difference of opinion among the members, the opinion of the majority shall prevail;
  - (e) Each member of the Board of Management shall have one vote and if there be equality of votes on any question to be determined by the Board, the Chairperson of the Board of Management or, as the case may be, the member presiding over that meeting shall, in addition, have a casting vote;
  - (f) Every meeting of the Board of Management shall be presided over by the Chairperson, Board of Management and in his absence the meeting will be presided by a member elected by the members present;
  - (g) If urgent action by the Board of Management becomes necessary, the Chairperson, Board of Management may permit the business to be transacted by circulation of papers to the members of the Board of Management. The action so proposed to be taken shall not be taken unless agreed to by a majority of members of the Board. The action so taken shall be forthwith intimated to all the members of the Board. In case the authority concerned fails to take a decision, the matter shall be referred to the Chancellor, whose decision shall be final;
23. **The Academic Council** - (1) The Academic Council shall be the principal academic body of the University and shall, subject to the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances, have the control and regulations of, and be responsible for, the maintenance of standards of instruction, education, research and examination within the University and shall exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed upon it by the Statutes.
- (2) The Academic Council shall have the right to advise the Board on all academic matters.
  - (3) The Academic Council shall consist of the following members, namely-
    - (i) Chairperson: Vice-Chancellor (Ex-officio);
    - (ii) Pro Vice-Chancellor (Ex-officio);
    - (iii) Four persons, who are not employees of the university to be co-opted by the Academic Council on the recommendations of the Vice-Chancellor from amongst Educationists, Scientists or Engineers of repute;
    - (iv) A nominee of the University Grants Commission;
    - (v) A nominee of the All India Council for Technical Education;
    - (vi) A nominee of an Industry Association namely NASCOM / ASSOCHAM / FICCI, etc.;
    - (vii) All Deans of the University (Ex-Officio);

- (viii) All Heads of the Departments (Ex-Officio);
  - (ix) One Professor, one Associate Professor and one Assistant Professor of the University to be nominated by Vice-Chancellor on rotation basis;
  - (x) Such other members as may be prescribed by the Statutes;
  - (xi) Registrar (ex officio) - Member-Secretary.
- (4) The term of the members of the Academic Council, other than ex-officio members, shall be three years.
- 24. Powers, Functions and Meetings of the Academic Council -** (1) Subject to the provisions of this Act, Statutes, Ordinances and Regulations and Overall supervision of the Board of Management, the Academic Council shall manage the academic affairs and matters in the University and in particular shall have the following powers and functions, namely:-
- (i) to report on any matter referred or delegated to it by the Board of Management;
  - (ii) to make recommendations to the Board of Management with regard to the creation, abolition or classification of teaching posts in the University and the emoluments payable and the duties attached thereto;
  - (iii) to formulate and modify or revise schemes for the organization of the Departments and/or Centre (including creation of Department and/or Centre) and to assign to such Departments their respective subjects and also to report to the Board of Management as to the expediency of the abolition or sub-division of any Department or the combination of one Department with another;
  - (iv) to recommend arrangements for the instruction and examination of persons other than those enrolled in the University;
  - (v) to promote research within the University and to require from time to time, report on such research;
  - (vi) to consider proposals submitted by the departments on the academic activities;
  - (vii) to lay down policies for admissions to the University;
  - (viii) to recognize diplomas and degrees of other Universities and Institutions and to determine their equivalence in relation to the diplomas and degrees of the Universities;
  - (ix) to fix, subject to any conditions accepted by the Board of Management, the time, mode and conditions of the competition for Fellowship, Scholarship and other prizes and to recommend for award of the same;



- (x) to recommend arrangements for the conduct of examinations and the dates for holding them;
  - (xi) to declare and review the result of the various examinations or to appoint committees or officers to do so, and to make recommendations regarding the conferment or grant of degrees, honours, diplomas, licences, titles and marks of honour;
  - (xii) to recommend stipends, scholarships, medals and prizes and to make other awards in accordance with the regulations and such other conditions as may be attached to the awards;
  - (xiii) to approve or revise the syllabus for the prescribed courses of study and lists of prescribed or recommended text books and to decide for publishing of books by the University;
  - (xiv) to approve such forms and registers as are from time to time, required by the ordinances and regulations;
  - (xv) to formulate, from time to time, the desired standards of education to be adhered in drawing up the curriculum and syllabi for being taught in the University;
  - (xvi) to recommend a new course or enhancement in number of seats of the existing course to the Board of Management for final decision;
  - (xvii) to perform, in relation to academic matters, all such duties and to do all such acts as may be necessary for the proper carrying out of the provisions of this Act and the Ordinances and Regulations made there under.
- (2) (i) The Academic Council shall meet as often as may be necessary, but not less than two times, during an academic year.
- (ii) One half of the existing members of the Academic Council shall form the quorum for a meeting of the Academic Council;
  - (iii) In case of difference of opinion among the members, the opinion of the majority shall prevail;
  - (iv) Each member of the Academic Council, including the Chairperson of the Academic Council, shall have one vote and if there be an equality of votes on the Academic Council on any matter to be determined by the Academic Council, the Chairperson shall in addition, have a casting vote;
  - (v) Every meeting of the Academic Council shall be presided over by the Vice-Chancellor and in the absence of Vice-Chancellor, the Pro-Vice Chancellor will preside the meeting and in his absence, by a member chosen in the meeting to preside on occasion;

- (vi) If urgent action by the Academic Council becomes necessary, the Chairperson of the Academic Council may permit the business to be transacted by circulation of papers to the members of the Academic Council. The action proposed to be taken shall not be taken unless agreed to, by a majority of the members of the Academic Council. The action as taken shall forthwith be intimated to all the members of the Academic Council. In case the authority concerned fails to take a decision, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision shall be final.

**The Planning Board -** (1) There shall be constituted a Planning Board of the University to be the principal planning body of the University and shall also be responsible for monitoring the development of the University.

The constitution of the Planning Board, the term of office of its members and its powers and functions shall be such as may be prescribed.

**The Departments -** (1) There shall be such number of Departments of Studies and Research as the University may determine from time to time.

The constitution, powers and functions of a Department shall be such as may be prescribed.

**The Finance Committee -** (1) There shall be a Finance Committee consisting of the following:-

- (i) Chairperson: Chairman, Board of Management (Ex-officio);
- (ii) Vice-Chancellor (Ex-officio);
- (iii) Pro-Vice Chancellor (Ex-officio);
- (iv) Comptroller of Accounts, Govt. of NCT of Delhi;
- (v) Principal Secretary or Secretary, Technical Education, Govt. of NCT of Delhi (Ex-officio);
- (vi) Principal Secretary or Secretary, Finance, Govt. of NCT of Delhi (Ex-officio);
- (vii) Two Deans nominated by the Vice-Chancellor;
- (viii) Two Heads of Department by rotation based on seniority;
- (ix) Two other members nominated by the Board of Management from amongst its members of whom at least one should be an employee of the University;
- (x) Such other members as may be prescribed by the Statutes;
- (xi) Registrar (ex-officio) - Member-Secretary.

- (2) The term of the members of the Finance Committee other than the ex-officio members, shall be three years.
- (3) The functions and duties of the Finance Committee shall be as follows:-
- (a) to examine and scrutinize the annual budget of the University and to make recommendations on financial matters to the Board of Management;
  - (b) to consider proposals for new expenditure and to make recommendations to the Board of Management;
  - (c) all proposals relating to revision of grades, upgradation of the pay-scales and those items which are not included in the budget, shall be examined by the Finance Committee before they are considered by the Board of Management;
  - (d) to consider the annual accounts and the financial estimates of the University prepared by the Registrar and laid before the Finance Committee for approval and thereafter submitted to the Board of Management;
  - (e) the Finance Committee shall fix the limits for the total recurring and non-recurring expenditure for the year, based on income and resources of the University, and no expenditure shall be incurred by the University in excess of the limits so fixed, without the approval of the Finance Committee;
  - (f) to give its views and to make recommendations to the Board of Management on any financial question affecting the University either on its own initiative or on reference from the Board of Management.
  - (g) to recommend the investment of any money belonging to the University, including any unapplied income, in such stock, funds, shares or securities as it may, from time to time, think fit, or in the purchase or immovable property in India, with the like power of varying such investments from time to time
- (4) The Finance Committee shall meet, at least, four times in a year. Five members of the Finance Committee shall form the quorum at any meeting.
- (5) In case of difference of opinion among the members, the opinion of the majority of the members present shall prevail.
28. **Other Authorities** - The constitution, power and functions of the other authorities which may be declared by the Statutes to be the authorities of the University, shall be such as may be prescribed.

29. **Statutes** - Subject to the provision of this Act, the Statutes may provide for all or any of the following matters, namely:-
- (a) the constitution, powers and functions of the authorities and other bodies of the University, as may be found necessary to be constituted from time to time;
  - (b) the selection and continuance in office of the members of the authorities and bodies of the University, the filling up of vacancies of members and all other matters relating thereto which the university may deem necessary or desirable to provide;
  - (c) the appointing/ disciplinary authorities for all Groups A,B,C & D teaching and non-teaching employees of the University;
  - (d) terms and conditions for continuation of the teachers and other employees in the employment of the erstwhile Indira Gandhi Institute of Technology;
  - (e) the manner of appointment of the officers of the University, terms and conditions of their service, their powers and duties and emoluments;
  - (f) the manner of appointment of the teachers of the University, other academic staff, and other employees and their emoluments;
  - (g) the manner of appointment of teachers and other academic staff working in any other university/industry for a specified period for undertaking a joint project, their terms and conditions of service and emoluments;
  - (h) the terms and conditions of service of the teachers and other members of the academic staff appointed by the University;
  - (i) the terms and conditions of other employees appointed by the University;
  - (j) the constitution of the pension or the provident fund and the establishment of an insurance scheme for the benefit of the employees of the University;
  - (k) the principles governing the seniority of employees of the University;
  - (l) the procedure for any appeal by an employee or a student of the University;
  - (m) conferment of honorary degrees;
  - (n) institution of fellowships, scholarships, studentship, medals, prizes and other incentives;
  - (o) maintenance of discipline among the employees of the University;
  - (p) establishment of Chairs, Departments and Centre;
  - (q) management, supervision and inspection of institutions/centres established and/or maintained by the University;
  - (r) the delegation of powers vested in the authorities or the officers of the University;

- (s) all other matter which, by or under this Act, are to be, or may be, provided for by the Statutes.

**30. Statutes, how made –** (1) The first Statutes shall be those made by the Government with the prior approval of the Chancellor within thirty days of the commencement of this ACT.

- (2) The Board of Management may, from time to time, make new or additional Statutes or may amend or repeal the Statutes referred to in sub-section (1):

Provided that the Board of Management shall not make, amend or repeal any Statutes affecting the status, powers or constitution of any authority of the University until such authority has been given a reasonable opportunity of expressing its opinion in writing on the proposed change and any option so expressed within the time specified by the Board of Management has been considered by the Board of Management.

- (3) Every new Statute or addition to the Statutes or any amendment or repeal thereof shall require the approval of the Chancellor, who may assent thereto or withhold his assent or remit it to the Board of Management for reconsideration in the light of the observations, if any, made by him.

- (4) A new Statute or a Statute amending or repealing an existing Statute shall not be valid unless it has received the assent of the Chancellor, who will take into consideration the views of the concerned department while deciding the matter :

Provided that if the Chancellor does not convey his decision within sixty days of the reference received by him, it shall be deemed that the Chancellor has given his assent to the proposal.

**31. Ordinances -** (1) subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Ordinances may provide for all or any of the following matters, namely:-

- (a) the admission of students, the courses of study and the fees there for, the qualifications pertaining to the award of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions, the conditions for the grant of fellowship and awards and the like;
- (b) the conduct of examinations, including the terms and conditions of office and appointment of examiners;
- (c) the conditions of residence of students and their general discipline;
- (d) the management of institutions/centers maintained by the University;

- (e) the procedures for the settlement of disputes between the employees and the University, or between the students and the University;
- (f) the procedures for the settlement of disputes between the employees and students;
- (g) the procedure for any appeal by an aggrieved employee or a student;
- (h) maintenance of discipline among the students of the University;
- (i) regulation of the conduct and duties of the employees of the University and regulation of the conduct of the students of the University;
- (j) the categories of misconduct for which action may be taken under this Act or the Statutes or the Ordinances;
- (k) any other matter which, by or under this Act or the Statutes, is to be, or may be, provided for by the Ordinances.

- (2) The first Ordinance shall be made by the Vice-Chancellor with the prior approval of the Government and the Ordinance so made may be amended, repealed or added to, at any time by the Board of Management in such manner as may be prescribed.

32. **Regulations** - The authorities of the University may make regulations consistent with this Act, the Statutes and the Ordinances, in the manner prescribed by the Statutes for the conduct of their own business and that of the committees, if any, appointed by them and not provided for by this Act, the Statutes or the Ordinances.

33. **Annual Report** - (1) The annual report of the University shall be prepared under the directions of the Board of Management which shall include, among other matters, the steps taken by the University towards the fulfillment of its objects.

- (2) The annual report so prepared shall be submitted to the Chancellor within six months from the date of completion of the academic year.

- (3) A copy of the annual report, as prepared under sub-section (1), shall also be submitted to the Government which shall, as soon as may be, cause the same to be laid before the Legislative Assembly of Delhi.

34. **Annual accounts** - (1) The annual accounts and the balance sheet of the University shall be prepared under the direction of the Vice-Chancellor and approved by Board of Management and shall, at least once every year and at intervals of not more than fifteen months, be audited by the Comptroller and Auditor General of India or such person or such person or persons as he may authorize in this behalf.

- (2) A copy of the annual accounts together with the audit report shall be submitted to the Chancellor along with the observations, if any, of the Board of Management.
- (3) Any observation made by the Chancellor on the annual accounts shall be brought to the notice of the Board of Management.
- (4) A copy of the annual accounts together with the audit report as submitted to the Chancellor, shall also be submitted to the Government, which shall, as soon as may be, cause the same to be laid before the Legislative Assembly of Delhi.

**35. Conditions of service of employees -** (1) The University shall enter into a written contract of service with every new employee of the University appointed, on regular basis or otherwise and the terms and conditions of the contract shall not be inconsistent with the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances.

- (2) A copy of the contract referred to in sub-section (1) shall be lodged with the University and a copy thereof shall also be furnished to the employee concerned.

**36. Tribunal of Arbitration -** (1) Any dispute arising out of a contract of employment referred to in Section 35 between the University and the employee shall be referred to a Tribunal of Arbitration which shall consist of one member nominated by the Board of Management, one member nominated by the employee concerned and an umpire to be nominated by the Chancellor.

- (2) Every such reference shall be deemed to be a submission to arbitration on the terms of this section within the meaning to the Law of Arbitration as in force, and all the provisions of that Law, with the exception of section 2 thereof, shall apply accordingly.

- (3) The procedure for regulating the work of the Tribunal of Arbitration shall be such as may be prescribed by the University.

- (4) The decision of the Tribunal of Arbitration shall be final and binding on the parties, and no suit shall lie in any court in respect of any matter decided by the Tribunal.

**37. Provident and Pension Funds -** The University shall constitute for the benefit of its employees such provident fund and pension fund or provide such insurance scheme as it may deem fit in such manner and subject to such conditions as may be prescribed :

Provided that the existing employees shall continue to be governed by the existing pension and Provident Fund Schemes prevailing to their services in the Indira Gandhi Institute of Technology.

38. **Disputes as to the constitution of the University Authorities and Bodies** - If any question arises as to whether any person has been duly appointed as, or is entitled to be, a member of any authority or other body of the University, the matter shall be referred to the Chancellor with Board of Management recommendations whose decision thereon shall be final.
39. **Filling of casual vacancies** - All the casual vacancies among the members (other than ex-officio members) of any authority or other body of the University shall be filled, as soon as may be convenient, by the person or body who appoints, elects or co-opts the members whose place has become vacant and any person appointed, elected or co-opted to a casual vacancy shall be a member of such authority or body for the residue of the term for which the person whose place he fills, would have been a member.
40. **Proceedings of the University authorities or bodies not invalidated by vacancies** - No act or proceedings of any authority or other body shall be invalidated merely by reasons of the existence of any vacancy or vacancies among its members.
41. **Protection of action taken in good faith** - No suit or other legal proceeding shall lie in any court against the University or against any authority, officer or employee of the University or against any person or body of persons acting under the order of direction of any authority or officer or other employee of the University for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of the provision of this Act or the Statutes or the Ordinances.
42. **Mode of proof of the University record** - A copy of any receipt, application, notice, order, proceedings, resolution of any authority or committee of the University, or other documents in the possession of the University, or any entry in any register duly maintained by the University, if certified by the Registrar so designed shall, notwithstanding anything contained in the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872) or in any other law for the time being in force, shall be admitted as evidence of the matters and transaction specified therein, where the original thereof would, if produced, have been admissible in evidence.
43. **Power to remove difficulties** - If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order, published in the official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order be made under this section after the expiry of three years from the commencement of this Act.



**44. Transitional provisions -** Notwithstanding anything contained in this Act and the Statutes -

- (a) the first Vice-Chancellor, and the first Registrar, shall be appointed by the Chancellor and shall be governed by the terms and conditions of service specified by the Statutes;
- (b) the first Court and the first Board of Management shall be nominated by the Chancellor and shall hold office for a term of three years.

**45. Statutes and Ordinances to be published in the official Gazette and to be laid before the Legislature -** (1) Every Statute and Ordinance made under this Act shall be published in the official Gazette.

- (2) Every Statute and Ordinance made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before the House of the Legislative Assembly of Delhi while it is in session for a total period of thirty days which may be comprised in one session or two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, the House agrees in making any modification in the Statute or the Ordinance or the House agrees that the Statute or the Ordinance, as the case may be, should not be made, the Statute or the Ordinance shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that Statute or Ordinance as the case may be.

**46. Honorary degree -** If not less than two-third of the members of the Academic Council recommend that an honorary degree, or academic distinction be conferred on any person on the ground that he is, in their opinion, by reason of eminent attainment and position, fit and proper to receive such degree or academic distinction, the Chancellor may, by an order, decide that that the same may be conferred on the person recommended.

**47. Withdrawal of degree or diploma -** (1) The Board of Management may on the recommendation of the Academic Council and on approval of Chancellor, withdraw any distinction, degree, diploma or privilege conferred on, or granted to, any person, by a resolution passed by the majority of the total membership of the Board of Management present and voting at the meeting, if such person has been convicted by a court of law for an offence, which, in the opinion of the Board of Management, involves moral turpitude or if he has been guilty of gross misconduct.

- (2) No action under sub-section (1) shall be taken against any person unless he has been given an opportunity to show cause against the action proposed to be taken.
- (3) A copy of the resolution passed by the Board of Management shall be immediately sent to the person concerned.

- (4) Any person aggrieved by the decision taken by the Board of Management may appeal to the Chancellor within thirty days from the date of receipt of such resolution.
- (5) The decision of the Chancellor in such appeal shall be final.
48. **Discipline** - (1) The University shall maintain a strict discipline among students through its Proctorial Board. A faculty member of the rank of the Professor/Associate Professor shall be appointed as Proctor by the Vice-Chancellor and will hold office for a term of two years.
- (2) The Proctorial Board shall deal with all matters connected with the discipline of students and Vice-Chancellor shall be the final authority of award of any punishment including expulsion from the University.
49. **Deemed validity of appointments** - Notwithstanding anything contained in any other law or instrument having the force of law for the time being in force, the appointments made to any post in the University in accordance with the Statutes, the Ordinances and the Regulations shall be deemed to be valid and in accordance with law.
50. **Overriding effect** - The provisions of this Act, the Statutes, the Ordinance and the regulations made under there shall have effect notwithstanding anything inconsistent contained therewith in any other law or instrument having the force of law for the time being in force.
51. **Sponsored Schemes** - Whenever the University receives funds from any Government, the University Grant Commission or other agencies sponsoring a scheme to be executed by the University, notwithstanding any thing in this Act or the Statutes or the Ordinance made there under:-
- (a) the amount received shall be kept by the University separately from the University Fund and utilized only for the purpose of the scheme ; and
- (b) the staff required to execute the scheme shall be recruited in accordance with the terms and conditions stipulated by the sponsoring organization.
52. **Power to issue directions** - The Chancellor may either *suo motu* or on the recommendation of the Board of Management may issue such directions as may be necessary or expedient in the interest of administration, financial or academic functioning of the University and in particular to ensure peace and tranquility in the University and to protect the property of the University.

(Tarun Sahrawat)  
Addl. Secretary (Law, Justice & L.A.)

फा. सं. 14(2)/एलए-2012/Cons2law/123.—भारत के राष्ट्रपति की दिनांक 4 जुलाई, 2012 को मिली अनुमति के पश्चात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जन साधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :—

**"न्यायालय शुल्क (दिल्ली संशोधन) अधिनियम, 2012  
(2012 का दिल्ली अधिनियम 11)**

(4 जून, 2012 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)

न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रवर्तन के लिए आगे संशोधन हेतु अधिनियम।

[4 जुलाई, 2012]

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :— (1) यह अधिनियम न्यायालय शुल्क (दिल्ली संशोधन) अधिनियम, 2012 कहा जायेगा।

(2) यह समस्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लागू होगा।

(3) यह सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निश्चित तिथि से लागू होगा।

2 धारा 26 संशोधन :— राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा प्रवृत्त न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 (जिसे इसे पश्चात् "मुख्य अधिनियम" कहा गया है) की धारा 26 को पुनः क्रमांकित करके उसे उसकी उपधारा (1) किया जाएगा तथा इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :—

"(2) उपधारा (1) तथा धारा 25 के उद्देश्यों के लिए "स्टाम्प" का अर्थ है किसी ऐसे व्यक्ति या एजेंसी से जिसे समुचित सरकार ने अधिकृत किया है का कोई चिन्ह, मोहर या पृष्ठांकन तथा इसमें इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रभाय न्यायालय शुल्क के उद्देश्य से चिपकाई जाने वाली या अंकित स्टाम्प भी शामिल हैं।

स्पष्टीकरण:— "अंकित स्टाम्प" में फ्रेकिंग मशीन या कोई अन्य मशीन या ई-स्टाम्पिंग या समान शॉफ्टवेयर द्वारा लगाया गया कोई यूनिक नम्बर शामिल है जैसा कि समुचित सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

3 अनुसूचि-1 तथा अनुसूचि-2 के लिए नयी अनुसूचि का प्रतिस्थापन:— मुख्य अधिनियम में अनुसूचि-1 तथा अनुसूचि-2 के लिए क्रमशः निम्नलिखित अनुसूचि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

## “ अनुसूची -1

( राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा प्रवृत्त)

यथा मूल्य शुल्क

संख्या	संख्या	संख्या	संमुचित शुल्क
1.	वाद पत्र, लिखित वचन, अभिवचन, मुजराई या प्रतिदावा या अपील का ज्ञापन (न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 (1870 का 7) की किसी अनुसूची के अन्तर्गत अन्यथा उपबंधित नहीं) या धारा 8 में उल्लिखित को छोड़कर किसी दीवानी अदालत या राजस्व अदालत में प्रस्तुत प्रत्याक्षेप का	जब विषय वस्तु की राशि या मूल्य विवादित हो— (i) पचास हजार रुपये तक  (ii) पचास हजार एक रुपये से बीस लाख रुपये तक  (iii) बीस लाख रुपये से ऊपर	(i) उस राशि का मूल्य का दो प्रतिशत या एक हजार रुपये जो ज्यादा हो;  (ii) उस राशि या मूल्य का तीन प्रतिशत;  (iii) उस राशि का चार प्रतिशत
2.	विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 (1963 का 47) की धारा 6 के अन्तर्गत कब्जे के लिए वाद में वाद पत्र		पिछले मानदंड (अनुच्छेद -1 के अनुसार) में उल्लिखित राशि का आधा
3.	परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 (1881 का 26) की धारा 138 के अन्तर्गत शिकायत		पिछले मानदंड में यथानिर्धारित (अनुच्छेद-1 के अनुसार) लिखित के मूल्य के आधार पर परिकलित
4.	अचल संयुक्त संपत्ति के बंटवारे का मुकदमा	दीवानी अदालत जिसमें उच्च न्यायालय भी शामिल है की मूल शाखा के सामने दायर (आर्थिक क्षेत्राधिकार के अनुसार)	संपत्ति के बाजार मूल्य के अनुसार इस अनुसूची के अनुच्छेद-1 के अनुसार समुचित परन्तु न्यूनतम न्यायालय शुल्क एक हजार रुपये।
5.	निर्णय पर पुनर्विचार के लिए प्रार्थना पत्र यदि डिक्री की तिथि से नब्बे दिन तक या उसके पश्चात् प्रस्तुत की		वाद पत्र या अपील के ज्ञापन पर उद्ग्रहित शुल्क
6.	निर्णय पर पुनः विचार के लिए प्रार्थना पत्र यदि डिक्री की तिथि से नब्बे दिन		वाद पत्र या अपील के ज्ञापन पर उद्ग्रहित

	तक या उसके पश्चात् प्रस्तुत की		शुल्क
7.	निर्णय या आदेश के अनुवाद की प्रति जो डिक्री के समान या डिक्री की तरह प्रभावी नहीं होगा।	जब ऐसा निर्णय या आदेश उच्च न्यायालय को छोड़कर कोई दीवानी न्यायालय या किसी राजस्व न्यायालय का पीठासीन अधिकारी या राजस्व न्यायालय का अधिकारी या कार्यालय या कोई अन्य न्यायिक कार्यकारी प्राधिकारी पारित करे।  जब ऐसा निर्णय आदेश उच्च न्यायालय पारित करे।	दस रुपये प्रति पृष्ठ  बीस रुपये प्रति पृष्ठ
8.	डिक्री या आदेश जो डिक्री के समान लागू होता है	जब ऐसा निर्णय या डिक्री उच्च न्यायालय को छोड़कर किसी दीवानी न्यायालय या किसी राजस्व न्यायालय ने पारित किया है।  जब ऐसा निर्णय या डिक्री उच्च न्यायालय ने पारित की है।	दस रुपये प्रति पृष्ठ  बीस रुपये प्रति पृष्ठ
9.	किसी ऐसे दस्तावेज की प्रति जिस पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अन्तर्गत स्टाम्प ड्यूटी उद्ग्रहीत है, मूल को वापिस लेकर उसके स्थान पर किसी पक्ष द्वारा मुकदमें के लिए छोड़ा है, बशर्ते कि उस प्रति पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अंतर्गत कोई शुल्क नहीं लगता।	(क) जब मूल पर प्रमार्य स्टाम्प ड्यूटी एक रुपये से अधिक न हो  (ख) किसी अन्य मामले में	एक रुपया  दस रुपये
10.	किसी राजस्व या न्यायिक कार्यवाही या आदेश जिसका इस अधिनियम में प्रावधान नहीं है या किसी लेखा, बयान, रिपोर्ट या किसी दीवानी या फौजदारी या राजस्व न्यायालय के कार्यालय या किसी ऐसे मुख्य अधिकारी के कार्यालय से जिसे किसी मंडल के कार्यकारी प्रशासन का प्रभार प्राप्त है, वगैरह प्रति	प्रत्येक तीन सौ साठ शब्द या तीन सौ साठ शब्द के किसी भाग के लिए	दस रुपये
11.	किसी वसीयत का प्रोबेट या वसीयत के साथ या संलग्न वसीयत के बिना	जब ऐसी संपत्ति की राशि या मूल्य जिसका प्रोबेट या शासन	ऐसी राशि या मूल्य का

	<p>शासन पत्र</p>	<p>पत्र किया गया है, एक लाख रुपये से अधिक परन्तु दस लाख रुपये से अधिक नहीं है।</p> <p>जब राशि या मूल्य दस लाख रुपये के अधिक परन्तु पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है</p> <p>जब राशि या मूल्य पचास लाख रुपये से अधिक है</p> <p>उपबंध है कि जब भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 या 1827 का बम्बई संहिता विनियम सं० 8 के अंतर्गत किसकी संपदा में सम्पत्ति शामिल है जब उस संपत्ति के बारे में प्रोबेट या शासन पत्र किया जायेगा पत्र प्रदान करने के विषय में देय शुल्क में से पहले प्रदान की गई राशि को घटा दिया जायेगा।</p>	<p>ढाई प्रतिशत।</p> <p>ऐसी राशि या मूल्य का सवा तीन प्रतिशत</p> <p>ऐसी राशि या मूल्य का चार प्रतिशत।</p>
12.	<p>भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) के भाग-X के अंतर्गत प्रमाण पत्र</p>		<p>अधिनियम की धारा 374 के अंतर्गत प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट राशि या किसी ऋण या प्रतिभूति की राशि या मूल्य का चार प्रतिशत जिसका प्रमाण पत्र अधिनियम की धारा 376 के अंतर्गत विस्तारित है।</p> <p>नोट:- (1) ऋण की राशि इसकी ब्याज सहित वह राशि है जो प्रमाण पत्र में ऋण को शामिल करने के लिए आवेदन के दिन होती है जहां तक इस राशि को</p>

			<p>निर्धारित किया जा सकता है।</p> <p>(2) अधिनियम के अंतर्गत किसी प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट प्रतिभूति के विषय में कोई अधिकार प्रदान किया गया अथवा नहीं और जहां यह अधिकार ब्याज प्राप्त करने या लाभांश प्राप्त करने या मोलभाव करने या अंतरण के लिए है, दोनों उद्देश्यों की प्रतिभूति का मूल्य उसका वह बाजार मूल्य है जो उस दिन है जब प्रतिभूति को प्रमाण पत्र में शामिल करने के लिए आवेदन किया गया था जहां तक इस राशि को निर्धारित किया जा सकता है।</p>
13.	<p>दिल्ली उच्च न्यायालय में प्रयुक्ति हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 की धारा 44 के अंतर्गत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने या दिल्ली के उपराज्यपाल के न्यायालय को पंजाबी किरायेदारी अधिनियम, 1887 (1887 का 16) की धारा 84 के अंतर्गत अपनी पुनर्विचार अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने हेतु आवेदन पत्र</p>	<p>जब विवादस्पद विषय की राशि या मूल्य पचास हजार रुपये से अधिक नहीं है।</p> <p>जब यह राशि या मूल्य पचास हजार रुपये से अधिक है</p>	<p>एक सौ रुपये</p> <p>अपील के ज्ञापन पर उदग्राह्य शुल्क ”</p>

"अनुसूची-II  
(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा प्रवृत्त)  
निश्चित शुल्क

1.	<u>संख्या</u> आवेदन या याचिका	<u>समुचित शुल्क</u>
		<p>(क) सीमाकर या आबकारी विभाग के अधिकारी या सरकार से संपर्क रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किसी मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत तथा जब आवेदन की विषय-वस्तु पूर्णतः इस संपर्क से संबन्ध रखता है।</p> <p align="center">या</p> <p>अस्थायी चकबंदी भूमि को सरकार से सीधा संपर्क के अधीन स्वामित्व में रखने वाले व्यक्ति द्वारा किसी भू-राजस्व अधिकारी को प्रस्तुत तथा जब आवेदन या याचिका की विषय वस्तु केवल ऐसे व्यवहार से संबंधित हो।</p> <p align="center">या</p> <p>जब तत्समय लागू किसी अधिनियम के अन्तर्गत किसी स्थान के संरक्षण या सुधार के लिए किसी नगर निगम आयुक्त को प्रस्तुत की गई हो यदि आवेदन या याचिका केवल ऐसे संरक्षण या सुधार से संबंधित हो;</p> <p align="center">या</p> <p>जब किसी मुकद्दमें या मामले के बारे में जिसकी विषय वस्तु पचास रुपये से कम हो किसी मूल अधिकार क्षेत्र वाले प्रमुख दीवानी न्यायालय को छोड़कर किसी दीवानी न्यायालय में या 1865 के अधिनियम सं० 11 या 1868 के अधिनियम सं० 16 के</p>



		<p>अन्तर्गत गठित लघुवाद न्यायालय को या कलेक्टर या राजस्व के किसी अधिकारी को प्रस्तुत किया हो</p> <p>या</p> <p>जब किसी दीवानी, फौजदारी या राजस्व न्यायालय को प्रस्तुत किया गया या किसी न्यायालय, बोर्ड या अधिकारी द्वारा पारित किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के अनुवाद की प्रति प्राप्त करने के लिए या ऐसे न्यायालय या कार्यालय में रिकार्ड में रखे गए किसी अन्य दस्तावेज के लिए।</p> <p>(ख) जब शिकायत की गई हो या अपराध के अलावा किसी अपराध के आरोप के लिए पुलिस अधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अन्तर्गत वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है और किसी फौजदारी अदालत में प्रस्तुत कर सकता है;</p> <p>या</p> <p>जब सिविल अपराधिक या राजस्व न्यायालय या कलेक्टर या किसी राजस्व अधिकारी जिसकी अधिकारिता संमान हो या कलेक्टर का अधीनस्थ हो या उसकी कार्यकारी क्षमता का कोई दंडाधिकारी और अन्यथा इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त;</p> <p>या</p> <p>न्यायालय में जमा कराया जाने वाला राजस्व या किराया;</p>	<p>दस रुपये</p> <p>दस रुपये</p>
--	--	---	---------------------------------

		<p>या</p> <p>न्यायालय द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि का मू-स्वामी द्वारा किराएदार को भुगतान।</p> <p>(ग) जब मुख्य आयुक्त या अन्य मुख्य नियंत्रक, राजस्व या कार्यकारी प्राधिकरण या राजस्व या सर्किट के आयुक्त या मंडल के कार्यकारी प्रशासन के साथ किसी मुख्य प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत किया जाए और अन्य इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त अन्यथा नहीं;</p> <p>(घ) जब उच्च न्यायालय को प्रस्तुत किया जाए—</p> <p>(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत याचिका के अलावा बन्दी प्रत्यक्षीकरण के लिए तथा दंड प्रक्रिया के लिए आने वाली याचिका;</p> <p>(ii) अधिकार लेख चार्टर के अंतर्गत अधिकार लेख अपील;</p> <p>(iii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत;</p> <p>(iv) अन्य सभी मामलों में विशेष रूप से उपलब्ध नहीं है।</p>	<p>दस रुपये</p> <p>एक सौ रुपये</p> <p>एक सौ रुपये</p> <p>एक सौ रुपये</p> <p>दो सौ रुपये</p>
2.	किसी सिविल न्यायालय को आवेदन कि रिकार्ड किसी अन्य न्यायालय से मंगवाया जाए	जब न्यायालय आवेदन पर अपने विचार देता है कि ऐसे रिकार्ड का प्रेषण पोस्ट के प्रयोग पर सम्मिलित है।	इस अनुसूची के अनुच्छेद-1 के खंड (क) खंड (ख) या खंड (घ) के अन्तर्गत आवेदन पर उगाही फीस के अलावा दस प्रतिशत।

3.	वाद में अपील का वाद-पत्र या ज्ञापन ताकि दखल के अधिकारी को स्थापित या असत्यसिद्ध करना।		एक सौ पच्चीस रुपये
4.	तलाक अधिनियम 1869 (1869 का 4) की धारा 49 के अन्तर्गत वचनबद्ध।		एक सौ पच्चीस रुपये
5.	अपील का ज्ञापन जब अपील डिक्री से न हो या डिक्री के फोर्स का आदेश हो और उसे प्रस्तुत किया गया हो।	(क) उच्च न्यायालय के अलावा कोई सिविल न्यायालय या किसी राजस्व न्यायालय को या उच्च न्यायालय के अलावा कार्यकारी अधिकारी या मुख्य राजस्व नियंत्रक या कार्यकारी प्राधिकारी।  (ख) उच्च न्यायालय को या मुख्य आयुक्त या मुख्य कार्यकारी नियंत्रक या राजस्व प्राधिकारी।	दस रुपये  बीस रुपये
6.	विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (1954 का 43) या हिन्दु विवाह अधिनियम, 1955 (1955 का 25) या मुस्लिम विवाह अधिनियम, 1939 (1939 का 8) का विघटन के अंतर्गत प्रत्येक याचिका या आवेदन या अपील का ज्ञापन		एक सौ पचास रुपये
7.	निम्न प्रत्येक वाद में अपील का वाद या ज्ञापन:- (i) अधिकार-लेख या किसी राजस्व न्यायालय द्वारा गैर स्थापित सिविल न्यायालय के सार निर्णय को बदलना या अलग करना या आदेश देना;  (ii) राजस्व अदा करने वाले संपदा के मालिक के नाम की रजिस्टर में किसी प्रविष्टि को बदलना या रद्द करना;  (iii) घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने के लिए जहां अनुवर्ती सहायता की प्रार्थना न की गई हो;  (iv) गोद लेने को अलग करना;		दो सौ रुपये  दो सौ रुपये  दो सौ रुपये  एक सौ पचास रुपये

	(v) अन्य प्रत्येक वाद जहां राशि का मूल्यांकन संभव नहीं है वहां विषय मामला विवादित है और न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (1870 का 7) की अनुसूची के द्वारा कोई अन्यथा उपलब्ध हो।		एक सौ पचास रुपये
8(क)	माध्यस्थता के अंतर्गत आवेदन तथा सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26)		
	(i) धारा 11 के अन्तर्गत माध्यस्थता की नियुक्ति के लिए	जब इनके समक्ष हो— (i) सिविल न्यायाधीश; (ii) जिला न्यायाधीश; (iii) उच्च न्यायालय;	दो सौ पचास रुपये पाँच सौ रुपये एक हजार रुपये
	(ii) धारा 27 के अन्तर्गत गवाही लेने के लिए न्यायालय की सहायता के लिए।	जब इनके समक्ष हो— (i) सिविल न्यायाधीश; (ii) जिला न्यायाधीश; (iii) उच्च न्यायालय;	दो सौ पचास रुपये पाँच सौ रुपये एक हजार रुपये
	(iii) धारा 36 के अन्तर्गत पुरस्कार हेतु प्रवर्तन मांगने हेतु।	जब इनके समक्ष हो— (i) सिविल न्यायाधीश; (ii) जिला न्यायाधीश; (iii) उच्च न्यायालय;	एक हजार रुपये या निर्णित की गई राशि का एक प्रतिशत। इनमें से जो ज्यादा हो।
	(iv) धारा 34 के अन्तर्गत माध्यस्थता पुरस्कार निर्धारित करने के लिए	जब इनके समक्ष हो— (i) सिविल न्यायाधीश; (ii) जिला न्यायाधीश; (iii) उच्च न्यायालय;	एक हजार रुपये या निर्णित की गई राशि का एक प्रतिशत। इनमें से जो ज्यादा हो।
8(ख)	धारा 37 के अन्तर्गत अपील का ज्ञापन		एक हजार रुपये या निर्णित की गई राशि का एक प्रतिशत। इनमें से जो ज्यादा हो।
9.	सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अन्तर्गत न्यायालय के मत के लिए प्रश्न पूछने हेतु लिखित में अनुबंध।		एक सौ पचास रुपये

10.	तलाक अधिनियम, 1869 (1869 का 4) के अन्तर्गत प्रत्येक याचिका, इसी अधिनियम की धारा 44 के अन्तर्गत याचिका को छोड़कर तथा इसी अधिनियम की धारा 56 के अन्तर्गत प्रत्येक अपील का ज्ञापन।		एक सौ पचास रुपये
11.	पारसी विवाह एवं तलाक अधिनियम, 1936 (1936 का 3) के अन्तर्गत वाद या अपील का ज्ञापन।		एक सौ पचास रुपये
12.	पैतृक भूमि के हस्तांतरण के संबंध में घोषणा के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लागू किसी रूढ़िगत कानून के अन्तर्गत संशोधन वाद द्वारा वाद में वाद या अपील का ज्ञापन।		एक सौ पचास रुपये
13.	दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 (1958 का 59) के अन्तर्गत सहायता के लिए आवेदन या अपील का ज्ञापन।		एक सौ पचास रुपये
14.	बैंकिंग कंपनी अधिनियम, 1949 (1949 का 10) के अन्तर्गत राशि का दावा के लिए (चाहे सुरक्षित या असुरक्षित) या ऐसे दावों के विरुद्ध दावा करना।	(क) जहां राशि दो हजार पाँच सौ रुपये से अधिक न हो।  (ख) जहां राशि दो हजार पाँच सौ रुपये से अधिक हो परन्तु दस हजार रुपये से अधिक न हो।  (ग) जहां राशि दस हजार रुपये से अधिक हो।	एक सौ पचास रुपये  दो सौ पचास रुपये  पाँच सौ रुपये
15.	बैंकिंग कंपनी अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 45 बी के प्रावधानों के तहत पारित आदेश या निर्णय से अपील का ज्ञापन।	(क) जहां राशि पाँच हजार रुपये से अधिक हो परन्तु दस हजार रुपये से अधिक न हो।  (ख) जहां राशि दस हजार रुपये से अधिक हो।	एक हजार रुपये  एक हजार पाँच सौ रुपये
16.	किसी निर्णय के प्रवर्तन में निष्पादन याचिका मांगना	(क) जब सिविल न्यायाधीश के समक्ष दायर हो;	दो सौ पचास रुपये

		(ख) जब जिला न्यायाधीश के समक्ष दायर हो;	पाँच सौ रुपये
		(ग) जब उच्च न्यायालय के समक्ष दायर	एक हजार रुपये
17.	सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 24 के अन्तर्गत या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 402 से 411 तक के अंतर्गत स्थानान्तरण याचिका।	(क) जब सत्र न्यायाधीश/जिला न्यायाधीश के समक्ष दायर हो;	पाँच सौ रुपये
		(ख) जब उच्च न्यायालय के समक्ष दायर हो;	एक हजार रुपये
		(ग) जब मुख्य दंडाधिकारी के समक्ष दायर	दो सौ पचास रुपये
18.	जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) के अभ्यावेदन के अंतर्गत चुनाव याचिका।		पाँच हजार रुपये
19.	उच्च न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 482 के अंतर्गत याचिका।		दो सौ पचास रुपये
20.	दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 397 के अंतर्गत दंड पुनरीक्षण याचिका।	जब उच्च न्यायालय के समक्ष दायर हो।	एक सौ रुपये
		जब सत्र न्यायाधीश के समक्ष दायर हो।	पचास रुपये
21.	उच्च न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 401 के अंतर्गत दंड पुनरीक्षण याचिका।		एक सौ रुपये
22.	दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 437 या धारा 438 के अन्तर्गत जमानत आवेदन।	जब उच्च न्यायालय के समक्ष दायर हो।	दो सौ पचास रुपये
		जब सत्र न्यायाधीश के समक्ष दायर हो।	एक सौ रुपये
		जब दंडाधिकारी के समक्ष दायर हो।	पचास रुपये

23.	सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के आदेश 43 के साथ पढ़ा गया धारा 104 के अंतर्गत आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील।	जब उच्च न्यायालय के समक्ष दायर हो।  जब किसी अन्य न्यायालय के समक्ष दायर हो, अधिकारियों अपील का प्रयोग।	दो सौ पचास रुपये  एक सौ पचास रुपये
24.	कंपनी अधिनियम 1956(1956 का 1) के अन्तर्गत - (i) उपरोक्त अधिनियम के भाग- vii के अध्याय- ii के अंतर्गत कंपनी को समाप्त करने संबंधी कोई प्रक्रिया  (ii) उक्त अधिनियम के छठे भाग के अध्याय-v के अन्तर्गत किसी प्रकार के समझौता प्रबंध, पुनर्निर्माण या एकीकरण की किसी योजना के लिये न्यायालय की स्वीकृति हेतु किसी प्रकार की कार्रवाई के लिये  (iii) अत्याचार तथा/अथवा कुप्रबंधन की रोकथाम के लिये उक्त अधिनियम के भाग-vi के अध्याय-vi के अन्तर्गत किसी प्रकार की अन्य न्यायिक कार्रवाई  (iv) किसी प्रकार की न्यायिक कार्रवाई करने के लिये उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कोई अन्य याचिका  (v) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अन्तर्गत कोई अपील		दो हजार पाँच सौ रुपये  दो हजार पाँच सौ रुपये  दो हजार पाँच सौ रुपये  दो सौ पचास रुपये  पाँच सौ रुपये
25.	आपात सूचना/चेतावनी	जब किसी सिविल न्यायाधीश के समक्ष दायर किया गया।  जब किसी जिला न्यायाधीश के समक्ष दायर किया गया।  जब उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया	एक सौ रुपये  दो सौ पचास रुपये  पाँच सौ रुपये

26.	न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 (1971 का 70) के अन्तर्गत अवमानना याचिका		एक सौ रुपये
27.	न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 (1971 का 70) के अन्तर्गत अपील		एक सौ रुपये
28.	मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत दावा याचिका	मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण के समक्ष दायर	एक सौ रुपये
29.	किसी मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 57) के अन्तर्गत अपील		दो सौ पचास रुपये
30.	बुद्धिजीवी संपत्ति अधिकार के अन्तर्गत कोई वाद या याचिका	जब किसी सिविल न्यायाधीश के समक्ष दायर की जाए  जब किसी जिला न्यायाधीश के समक्ष दायर की जाए  जब उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की जाए	पाँच सौ रुपये  एक हजार रुपये  पाँच हजार रुपये
31.	आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या संपत्ति कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के अन्तर्गत या संबंधित अपील		पाँच हजार रुपये
32.	सीमित दायित्व सहभागिता अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत लेखाओं की व्याख्या हेतु तथा/अथवा विभाजन किसी प्रकार की राहत के लिये सहभागिता अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के अन्तर्गत कोई वाद	जब किसी सिविल न्यायाधीश के समक्ष दायर की जाए  जब किसी जिला न्यायाधीश के समक्ष दायर की जाए  जब उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की जाए	एक सौ रुपये या वाद के मूल्य का एक प्रतिशत जो भी अधिक हो  दो सौ पचास रुपये या वाद मूल्य का एक प्रतिशत जो भी अधिक हो  पाँच सौ या वाद के मूल्य का एक प्रतिशत, जो भी अधिक हो



33.	उच्च न्यायालय के समक्ष दायर सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 115 के अन्तर्गत संशोधन याचिका		पाँच सौ रुपये
34.	उच्च न्यायालय के समक्ष दायर सनदों भाड़ा नियंत्रक या भाड़ा नियंत्रण न्यायाधिकरण के आदेश के विरुद्ध दिल्ली भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 1958 (1958 का 59) के अन्तर्गत दायर संशोधन याचिका		पाँच सौ रुपये
35.	उक्त के अन्तर्गत न आने वाली/वाला कोई याचिका या बाद	जब किसी सिविल न्यायाधीश के समक्ष दायर की जाए  जब किसी जिला न्यायाधीश के समक्ष दायर की जाए  जब उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की जाए	एक सौ रुपये  दो सौ पचास रुपये  पाँच सौ रुपये ”

तरुन सहरावत, अतिरिक्त सचिव

F. No. 14(2)/LA-2012/Cons2law/123.—The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the President of India on 4th July, 2012 and is hereby published for general information :—

**“THE COURT-FEES (DELHI AMENDMENT) ACT, 2012  
(DELHI ACT 11 OF 2012)**

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 4<sup>th</sup> June, 2012)

[ 4<sup>th</sup> July, 2012]

An Act further to amend the Court-Fees Act, 1870 in its application to the National Capital Territory of Delhi.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:—

1. **Short title, extent and commencement.** — (1) This Act may be called the Court Fees (Delhi Amendment) Act, 2012.
- (2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.
- (3) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the official Gazette, appoint.

2. **Amendment of section 26.**— In the Court Fees Act, 1870 as in force in the National Capital Territory of Delhi (hereinafter referred to as “the principal Act”), section 25 shall be re-numbered as sub-section (1) thereof, and after sub-section (1) as so re-numbered, the following sub-section shall be inserted, namely:—

12685 D6/12-10

"(2) For the purposes of sub-section (1), and section 25, "stamp" means any mark, seal or endorsement by any agency or person duly authorized by the Appropriate Government; and includes an adhesive or impressed stamp, for the purposes of court fee chargeable under this Act.

Explanation.-"impressed stamp" includes impression by a franking machine or any other machine, or a unique number generated by e-stamping or similar software, as the Appropriate Government may, by notification in the official Gazette, specify."

3. Substitution of new Schedules for the Schedule I and the Schedule II - In the principal Act, for the Schedule I and the Schedule II, the following Schedules shall respectively be substituted, namely:-

**- SCHEDULE I  
(AS APPLICABLE TO THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI)  
AD VALOREM FEES**

Number	Proper fee
1. Complaint, written statement, pleading, a set off or counterclaim or memorandum of appeal (not otherwise provided for under any of these Schedules of the Court Fees Act, 1870 (7 of 1870) or of cross objection presented to any Civil or Revenue Court except those mentioned in section 8.	When the amount or value of subject matter in dispute is - i) upto fifty thousand rupees; Two percentum on such amount or value or one thousand rupees whichever is more; ii) fifty thousand one rupees upto twenty lakh rupees; Three percentum on such amount or value; iii) above twenty lakh rupees; Four percentum on such amount or value.
2. Complaint in suit for possession under section 6 of the Specific Relief Act, 1963 (47 of 1963).	A fee of one-half the amount prescribed in the foregoing scale (vide Article I).
3. Complaint under section 138 of the Negotiable Instrument Act, 1881 (26 of 1881).	Same as prescribed in the foregoing scale (vide Article I) calculated in terms with value of the instrument.
4. Suit for partition of immoveable joint property	Filed before Civil Court including High Court at its original side, (as per pecuniary jurisdiction). Ad-velorem as per Article I of this Schedule calculated in accordance with market value of the property subject to minimum court fee of one thousand rupees.
5. Application for review of judgment, if presented on or after the ninetieth day from the date of the decree.	The fee leviable on the plaint or memorandum of appeal.

6. Application for review of judgment, if presented before the ninetieth day from the date of the decree. One-half of the fee leviable on the plaint or memorandum of appeal.
7. Copy of translation of judgment or order not being, or having the force of a decree. When such judgment or order is passed by any Civil Court other than a High Court, or by the Presiding Officer of any Revenue Court or Officer of any Revenue Court or Office or by any other Judicial Executive Authority. Ten rupees per page.  
When such judgment or order is passed by a High Court. Twenty rupees per page.
- Copy of decree or order having the force of a decree. When such decree or order is made by any Civil Court other than a High Court, or by any Revenue Court. Ten rupees per page.  
When such decree or order is made by a High Court. Twenty rupees per page.
9. Copy of any documents liable to stamp duty under the Indian Stamp Act, 1899, when left by any party to a suit or proceeding in place of the original withdrawn, provided such copy is not subject to any duty under the Indian Stamp Act, 1899. (a) When the stamp duty chargeable on the original does not exceed one rupees. One rupees.  
(b) In any other case. Ten rupees.
10. Copy of any revenue or judicial proceeding or order not otherwise provided for by this Act, or copy of any account, statement, report or the like, taken out of any Civil or Criminal or Revenue Court or Office or from the office of any chief officer charged with the executive administration of a division. For every three hundred and sixty words or fraction of three hundred and sixty words. Ten rupees.
11. Probate of a Will or Letters of Administration with or without Will annexed. When the amount or value of the property in respect of which the grant of probate or letters is made exceeds one lakh rupees, but does not exceed ten lakh rupees. Two and one-half per centum on such amount or value.

When such amount or value exceeds ten lakh rupees, but does not exceed fifty lakh rupees. Three and one quarter per centum on such amount or value.

When such amount or value exceeds fifty lakh rupees. Four per centum on such amount or value.

Provided that when after the grant of a certificate under Part-X of the Indian Succession Act, 1925 (39 of 1925) or under the Regulation of the Bombay Code No.8 of 1827 in respect of any property included in an estate, a grant of probate or letters of administration is made in respect of the same estate, the fee payable in respect of the latter grant shall be reduced by the amount of the fee paid in respect of the former grant.

Certificate under Part-X of the Indian Succession Act, 1925 (39 of 1925)

Two and one-half per centum on the amount or value of any debt or security specified in the certificate under section 374 of the Act, and four per centum on the amount or value of any debt or security to which the certificate is extended under section 376 of the Act.

Note. — (1) The amount of a debt is its amount, including interest on the day on which the inclusion of the debt in the certificate is applied for, so far as such amount can be ascertained.

(2) Whether or not any power with respect to a security specified in a certificate has been conferred under the Act and where such a power has been so conferred, whether the power is for the receiving of interest or dividends on or for the negotiation or transfer of, the security or for both purposes, the value of the security is its market-value on the day on which the inclusion of the security in the certificate is applied for, so far as such value can be ascertained.

13. Application to the High Court of Delhi for the exercise of its Jurisdiction under section 44 of the Punjab

When the amount or value of the subject-matter in dispute does not exceed fifty thousand rupees.

One hundred rupees.

Courts Act, 1918 as extended to the National Capital Territory of Delhi or to the Court of the Lt. Governor of Delhi for the exercise of its revisional jurisdiction under section 84 of the Punjab Tenancy Act, 1887 (16 of 1887).

When such amount or value exceeds fifty thousand rupees.

The fee leviable on a memorandum of appeal. "

**" SCHEDULE II  
(AS APPLICABLE TO THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI)**

**FIXED FEES**

Number	Proper fee
1. Application or petition	<p>(a) When presented to any officer of the Customs or Excise Department or to any Magistrate by any person having dealings with the Government, and when the subject-matter of such application relates exclusively to those dealings;</p> <p style="text-align: center;">Or</p> <p>when presented to any officer of land revenue by any person holding temporarily settled land under direct engagement with Government and when the subject-matter of the application or petition relates exclusively to such engagement;</p> <p style="text-align: center;">Or</p> <p>when presented to any Municipal Commissioner under any Act, for the time being in force, for the conservancy or improvement of any place, if the application or petition relates solely to such conservancy or improvement;</p> <p style="text-align: center;">Or</p> <p>when presented to any Civil Court other than a principal Civil Court of original jurisdiction or to any Court of Small Causes constituted under Act No. 11 of 1865 or under Act No. 16 of 1868, section 20, or to a Collector or other officer of revenue in relation to any suit or case in which the amount or value of the subject-matter is less than fifty rupees;</p>

Or

when presented to any Civil, Criminal or Revenue Court, or to any Board or Executive Officer for the purpose of obtaining a copy or translation of any judgment, decree or order passed by such Court, Board or Officer, or of any other document on record in such Court or Office.

Ten rupees.

(b) When containing a complaint or charge of any offence other than an offence for which police officers may, under the Code of Criminal Procedure 1973 (2 of 1974), arrest without warrant, and presented to any Criminal Court;

Or

When presented to a Civil Criminal or Revenue Court or to a Collector or any Revenue Officer having jurisdiction equal or subordinate to a Collector, or to any Magistrate in his executive capacity, and not otherwise provided for by this Act;

Or

to deposit in Court revenue or rent; Ten rupees.

Or

for determination by a Court of the amount of compensation to be paid by land-lord to his tenant.

(c) When presented to a Chief Commissioner or other Chief Controller, Revenue or Executive Authority, or to a Commissioner of Revenue or Circuit, or to any Chief Officer charged with the executive administration of a Division and not otherwise provided for by this Act.

Ten rupees.

(d) when presented to the High Court -

(i) under article 226 of the Constitution of India other than petition for habeas corpus and petitions arising out of criminal proceedings;

One hundred rupees.

(ii) Letters Patent Appeal under the Letter Patent charter;

One hundred rupees.

- (iii) under article 227 of the Constitution of India; One hundred rupees.
- (iv) in all other cases not specifically provided. Two hundred fifty rupees.
2. Application to any Civil Court that records may be called for from another Court. When the Court grants the application and is of opinion that the transmission of such records involves the use of the post. Ten percentum in addition to the fee levied on the application under clause (a), clause (b) or clause (d) of Article-I of this Schedule. One hundred twenty five rupees.
- Plaint or memorandum of appeal in a suit to establish or disprove a right of occupancy.
- Undertaking under section 49 of the Divorce Act, 1869 (4 of 1869). One hundred twenty five rupees.
- Memorandum of appeal when the appeal is not from a decree or an order having the force of decree, and is presented. (a) to any Civil Court other than a High Court or to any Revenue Court or Executive Officer other than the High Court or Chief Controlling Revenue or Executive Authority. Ten rupees.
- (b) to the High Court or Chief Commissioner, or other Chief Controlling Executive or Revenue Authority. Twenty rupees.
6. Every petition or application or memorandum of appeal under the Special Marriage Act, 1954 (43 of 1954), or the Hindu Marriage Act, 1955 (25 of 1955) or the Dissolution of Muslim Marriage Act, 1939 (8 of 1939). One hundred fifty rupees..
7. Plaint or memorandum of appeal in each of the following suits :-
- (i) To alter or set aside a summary decision or order of any of the Civil Courts not established by Letters Patent or of any Revenue Court; Two hundred rupees.
- (ii) to alter or cancel any entry in a register of the names of proprietors of revenue paying estates; Two hundred rupees.
- (iii) to obtain a declaratory decree where no consequential relief is prayed; Two hundred rupees.
- (iv) to set aside an adoption; One hundred fifty rupees.

(v) every other suit where it is not possible to estimate at a money-value the subject-matter in dispute, and which is not otherwise provided for by any of the schedules of the Court Fees Act, 1870 (7 of 1870).

One hundred fifty rupees.

(a) Application under the Arbitration, and Conciliation Act, 1996 (26 of 1996)

(i) for appointment of Arbitrator under section 11;

When made before -  
i) a Civil Judge;

Two hundred fifty rupees.

ii) a District Judge;

Five hundred rupees.

iii) the High Court;

One thousand rupees.

(ii) for court assistance in taking evidence under section 27;

when made before -  
i) a Civil Judge;

Two hundred fifty rupees.

ii) a District Judge;

Five hundred rupees.

iii) the High Court;

One thousand rupees.

(iii) for seeking enforcement of an award under section 36;

when made before -  
i) a Civil Judge;

One thousand rupees or one percentum of the amount awarded in the Award, whichever is more.

ii) a District Judge;

iii) the High Court;

(iv) for setting aside the arbitral award under section 34;

When made before -  
i) a Civil Judge;

One thousand rupees or one percentum of the amount awarded, whichever is more.

ii) a District Judge;

iii) the High Court;

8.(b) Memorandum of appeal under section 37;

One thousand rupees or one percentum of the amount awarded, whichever is more.

9. Agreement in writing stating a question for the opinion of the Court under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)

One hundred fifty Rupees.



- Every petition under the Divorce Act, 1869 (4 of 1869) except petitions under section 44 of the same Act, and every memorandum of appeal under section 55 of the same Act.
- One hundred fifty rupees.
- Plaint or memorandum of appeal under the Parsi Marriage and Divorce Act, 1936 (3 of 1936).
- One hundred fifty rupees.
12. Plaint or memorandum of appeal in a suit by a reversioner under any customary law in force in the National Capital Territory of Delhi for declaration in respect of an alienation of an ancestral land.
- One hundred fifty rupees.
13. Application or memorandum of appeal for relief under the Delhi Rent Control Act, 1958 (59 of 1958).
- One hundred fifty rupees.
14. Claims for money (whether secured or unsecured) or a claim to set off made against such claims or counter-claims under the Banking Companies Act, 1949 (10 of 1949).
- (a) Where the amount does not exceed two thousand five hundred rupees. One hundred fifty rupees.
- (b) where the amount exceeds two thousand five hundred rupees but does not exceed ten thousand rupees. Two hundred fifty rupees.
- (c) where the amount exceeds ten thousand rupees. Five hundred rupees.
15. Memorandum of appeal from an order or decision passed under the provision of section 45B of the Banking Companies Act, 1949 (10 of 1949).
- (a) Where the amount exceeds five thousand rupees but does not exceed ten thousand rupees. One thousand rupees.
- (b) where the amount exceeds ten thousand rupees. One thousand five hundred rupees.
16. Execution petition seeking enforcement of any judgment, order or decree passed by any court.
- (a) When filed before a Civil Judge: Two hundred fifty rupees.
- (b) when filed before a District Judge: Five hundred rupees.
- (c) when filed before the High Court: One thousand rupees.

- |   |  |   |
|---|--|---|
|   | (a) When filed before Session Judge/District Judge.<br>(b) When filed before High Court.<br>(c) When filed before Chief Metropolitan Magistrate. | Five hundred rupees.<br>One thousand rupees.<br>Two hundred fifty rupees. |
| 18. Election petition under the Representation of People Act, 1951 (43 of 1951).  |  | Five thousand rupees.   |
| 19. Petition under section 482 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) before the High Court.   |  | Two hundred and fifty rupees.   |
| 20. Criminal Revision petition under section 397 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).   | when filed before the High Court.<br>when filed before a Sessions Judge.   | One hundred rupees.<br>Fifty rupees.                                      |
| 21. Criminal Revision Petition under section 401 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), before the High Court.                                |  | One hundred rupees.   |
| 22. Bail application under section 437 or section 438 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).  | When filed before the High Court.<br>when filed before a Sessions Judge.<br>when filed before a Metropolitan Magistrate.                         | Two hundred fifty rupees.<br>One hundred rupees.<br>Fifty rupees.         |
| 23. First Appeal against order under section 104 read with Order 43 of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).                                       | When filed before the High Court.<br>when filed before any other court exercising appellate jurisdiction.  | Two hundred and fifty rupees.<br>One hundred and fifty rupees.            |
| 24. Under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) -<br><br>(i) Any proceeding relating to winding up of a company under chapter II of part VII of the said Act. |  | Two thousand and five hundred rupees.                                     |

	(ii) For any proceeding seeking sanction of the court to the scheme of any compromise, arrangement, reconstruction or amalgamation etc. under chapter V of part VI of the said Act.		Two thousand and five hundred rupees.
	(iii) Any proceeding to prevent oppression and/or mismanagement or any other judicial action under chapter VI of part VI of the said Act.		Two thousand and five hundred rupees.
	(iv) Any other petition under the said Act for taking any judicial action		Two hundred and fifty rupees.
	(v) Any appeal under the Companies Act, 1956 (1 of 1956).		Five hundred rupees.
25.	Caveat application	When filed before a Civil Judge.	One hundred rupees.
		when filed before a District Judge.	Two hundred fifty rupees.
		when filed before the High Court.	Five hundred rupees.
26.	Contempt petition under the Contempt of Court Act, 1971 (70 of 1971).		One hundred rupees.
27.	Appeal under the Contempt of Court Act, 1971 (70 of 1971)		One hundred rupees.
28.	Claim petition under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988).	Filed before a Motor Accidents Claims Tribunal.	One hundred rupees.
29.	Appeal under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) against the award passed by a Motor Accidents Claims Tribunal.		Two hundred and fifty rupees.
30.	Any suit or petition under the Intellectual Property Rights.	When filed before a Civil Judge.	Five hundred rupees.

	when filed before a District Judge.	One thousand rupees.
	when filed before the High Court.	Five thousand rupees.
31.	Appeal relating to and under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).	Five thousand rupees.
32.	Any suit under the Partnership Act, 1932 (9 of 1932) for rendition of accounts and/or partition or for any relief under the Limited Liability Partnership Act, 2008.	When filed before a Civil Judge. One hundred or one per centum of the valuation of the suit, whichever is more;
	when filed before a District Judge.	Two hundred fifty or one per centum of the valuation of the suit whichever is more;
	when filed before the High Court.	Five hundred or one per centum of the valuation of the suit whichever is more.
33.	Revision petition under section 115 of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), filed before the High Court.	Five hundred rupees.
34.	Revision petition filed under the Delhi Rent Control Act, 1958 (59 of 1958) against the order of the Rent Controller or Rent Control Tribunal, filed before the High Court.	Five hundred rupees.
35.	Any other suit or petition not covered hereinabove	When filed before a Civil Judge. One hundred rupees.
	when filed before a District Judge.	Two hundred and fifty rupees.
	when filed before the High Court.	Five hundred rupees.

TARUN SAHRAWAT, Addl. Secy.

## राजस्व विभाग

## अधिसूचना

दिल्ली, 23 जुलाई, 2012

फा. सं. 7(1)/रा.वि./स.से.शा./रा.श./उपम. द./2012/पार्ट फा./1429. — सेवा विभाग, दिल्ली सरकार के आदेश सं. 180 दिनांक 26-4-2012 के सन्दर्भ में श्री एम. के. द्विवेदी, दानिक्स ने दिनांक 7-5-2012 (पूर्वाहन) को उप-मण्डलीय दण्डाधिकारी (डिफेंस कॉलेजी), जिला-दक्षिण का कार्यभार संभाल लिया है। अतः —

- (1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा लागू पंजाब भू-राजस्व अधिनियम 1887 (1887 का पंजाब अधिनियम संख्या 17) की धारा 27 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में, श्री एम. के. द्विवेदी, दानिक्स को, उस समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी की शक्तियों, अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान की जाती है।
- (2) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित उत्तरप्रदेश भू-राजस्व अधिनियम 1901 (1901 का अधिनियम संख्या 03) की धारा 223 के साथ पठित धारा 15 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में श्री एम. के. द्विवेदी, दानिक्स को, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत उस समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी के रूप में नियुक्त किया जाता है तथा उस समय तक कलैक्टर/सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी की शक्तियों, अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान की जाती है।
- (3) दिल्ली भू-राजस्व अधिनियम 1954 (1954 का अधिनियम संख्या 12) की धारा 76 के साथ पठित धारा 07 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा श्री एम. के. द्विवेदी, दानिक्स को, उस समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी तथा राजस्व सहायक के रूप में नियुक्त किया जाता है तथा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत उस समय तक कलैक्टर की सभी शक्तियों, अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जबतक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान की जाती है।
- (4) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा लागू उत्तरी भारत नहर तथा जल निकास अधिनियम 1873 (1873 का अधिनियम संख्या 02) की धारा 03 के खण्ड 6 के साथ पठित धारा 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में, श्री एम. के. द्विवेदी, दानिक्स को कलैक्टर के रूप में, सभी कार्यों को करने अथवा अधिरोधित करने के लिये, अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त किया जाता है।
- (5) दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम 1954 के अधिनियम संख्या 8 की धारा 3 के खंड 19 ए के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 परिशिष्ट में वर्णित राजस्व सहायक के कार्यों को निर्वहन करने के लिए श्री एम. के. द्विवेदी, दानिक्स को, उस समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी की शक्तियों, अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान की जाती है।
- (6) पूर्वी पंजाब जोत (चकबंदी तथा विखंडन रोकथाम) अधिनियम 1948 (1948 का पूर्वी पंजाब अधिनियम संख्या 50) की धारा 20 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए, श्री एम. के. द्विवेदी, दानिक्स को उस समय तक बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के रूप में, अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेशों तक इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त किया जाता है।
- (7) दिल्ली भूमि जोत (सीमाबंदी) अधिनियम 1960 (1960 का अधिनियम सं 0 24) की धारा 2 के खंड ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम के अंतर्गत उस समस्त क्षेत्र के लिए जहां लागू होता हो, के लिये सक्षम प्राधिकार का कार्य करने के लिये श्री एम. के. द्विवेदी, दानिक्स को, अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं अथवा अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्राधिकृत किया जाता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,  
कुलदीप सिंह गंगर, विशेष सचिव (राजस्व)

## REVENUE DEPARTMENT

## NOTIFICATION

Delhi, the 23rd July, 2012

F. No. 7(1)/Rev. Dept./GA br./Rev. P./SDM/2012/P.F./1429.—In pursuance of the Services Department's order No. 180 dated 26-4-2012, Shri M. K. Dwivedi, DANICS has joined as Sub-Divisional Magistrate (Defence Colony), Distt. South on 7-5-2012 (F/N). Now, therefore :—

1. In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 27 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 (Punjab Act No. XVII of 1887) as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby confers upon **Shri M. K. Dwivedi, DANICS** the power of Assistant Collector, 1st Class under the said Act within the National Capital Territory of Delhi, w.e.f date of assumption of charge and so long as he holds the Post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.
2. In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 15 read with 223 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901 (Act No. III of 1901) as extended to the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby appoints **Shri M. K. Dwivedi, DANICS** as Assistant Collector, 1st Class under the said Act within the National Capital Territory of Delhi, and confers upon him all the powers of Collector under the said Act within the National Capital Territory of Delhi, w.e.f date of assumption of charge and so long as he holds the Post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.
3. In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 7 read with 76 of the Delhi Land Revenue Act, 1954 (Act No. 12 of 1954) the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby appoints **Shri M. K. Dwivedi, DANICS** as Assistant Collector, 1st Class and Revenue Assistant in the National Capital Territory of Delhi and confers upon him all the powers of Collector under the said Act within the National Capital Territory of Delhi, w.e.f date of assumption of charge and so long as he holds the Post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.
4. In exercise of the powers conferred by Section 4 read with Clause 6 of Section 3 of the Northern India Canal & Drainage Act, 1873 (Act No. 2 of 1873) as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby appoints **Shri M. K. Dwivedi, DANICS** as Collector, to exercise or perform the duties conferred or imposed under the said Act within the National Capital Territory of Delhi, w.e.f date of assumption of charge and so long as he holds the Post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.
5. In exercise of powers conferred by Clause 19-A of Section 3 of the Delhi Land Reforms Act, 1954 (Act No. 8 of 1954) the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby empowers **Shri M. K. Dwivedi, DANICS** as Assistant Collector, 1st class to perform the function of Revenue Assistant described in the Schedule I as appended to the said Act within the National Capital Territory of Delhi, w.e.f date of assumption of charge and so long as he holds the Post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.
6. In exercise of the powers conferred by Sub Section (1) of Section 20 of East Punjab Holdings (Consolidation & Prevention of Fragmentation) Act 1948 (Act No. 50 of 1948) as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoints **Shri M. K. Dwivedi, DANICS** as Settlement Officer (Consolidation) for National Capital Territory of Delhi, w.e.f date of assumption of charge and so long as he holds the Post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.
7. In exercise of the powers conferred by Clause (c) of the Section 2 of the Delhi Land Holding (Ceiling) Act, 1960 (F.No. 24 of 1960) the Lt. Governor National Capital Territory of Delhi, is pleased to authorize **Shri M. K. Dwivedi, DANICS** to perform the function of the Competent Authority under the said Act within the whole areas to which the provision of the said act are applicable w.e.f date of assumption of charge and so long as he holds the Post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

By Order and in the Name of the Lt. Governor  
of National Capital Territory of Delhi,  
KULDEEP SINGH GANGAR, Spl. Secy. (Revenue)

## व्यापार एवं कर विभाग

( नीति शाखा )

## अधिसूचना

दिल्ली, 23 जुलाई, 2012

फा. सं. 7/453/नीति/वैट/2012/361-371.—मैं, राजेन्द्र कुमार, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, दिल्ली, दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 की धारा 19 की उप धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आदेश करता हूँ कि इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से अगले दो महीने के दौरान, ऐसे व्यापारियों को, जोकि विभाग के सम्मुख पंजीकरण के लिये आवेदन करते हैं, कोई प्रतिभूति प्रस्तुत करनी आवश्यक नहीं होगी।

राजेन्द्र कुमार, आयुक्त (मूल्य संवर्धित कर)

## DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES

(POLICY BRANCH)

## NOTIFICATION

Delhi, the 23rd July, 2012.

F. No. 7/453/Policy/VAT/2012/361-371.—I, Rajendra Kumar, Commissioner, Value Added Tax, Delhi, in exercise of powers conferred on me by sub-section (1) of Section 19 of Delhi Value Added Tax Act, 2004 hereby direct that no security would be required to be furnished by such dealers, who apply for registration with the department during the period of next two months from the date of issue of this notification.

RAJENDRA KUMAR, Commissioner (Value Added Tax)